



दैनिक जागरण

टी-20 विश्व कप में रोहित ही होंगे कप्तान >> 12



विश्वास News

13 हजार से ज्यादा कटियावाड़ फुड के 5 साल में विश्वास न्यूज की पहचाल • पेज-5

जागरण विशेष

सददेशी जैविक फिल्टर से कम होगा वाहनों का प्रदूषण



नई दिल्ली: गुणोत्कृष्ट जैव संस्थान ने ऐसा फिल्टर तैयार किया है जो वाहनों के धुएँ में मौजूद हानिकारक तत्वों को 80 प्रतिशत तक कम करने में सक्षम है।

संपादकीय

भारत-अमीरात की बेमिसाल जोड़ी: अमीरात में 'अहलन मोदी' का उद्घोष और बुर्ज खलीफा पर तिरंगे की रौनक दर्शा रही है कि यह मित्रता मजबूत होकर वैश्विक वैकल्पिक नेतृत्व में भूमिका निभाएगी। श्रीराम चव्हाण का वृद्धिकोण।

राजनीतिक इशकों वाला आंदोलन: प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को कुछ मांगें ऐसी हैं, जिन्हें किसी भी सरकार के लिए मानना सभ्य नहीं। उमेश चतुर्वेदी का आलेख।

विमर्श

नारी शक्ति के व्यापक योगदान की महत्ता: केंद्र सरकार द्वारा हालिया प्रस्तुत अंतरिम बजट में नारी शक्ति को महता और अर्थव्यवस्था में उनके व्यापक योगदान को दर्शाया गया है। मनु ल्यागी का विश्लेषण।

राज्यसभा में हिमाचल से सिंधवी का अभिषेक: हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस द्वारा अभिषेक मनु सिंधवी को राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी को राज्य और दलों में प्रदेश के समर्थित कार्यकर्ताओं-नेताओं की अनदेखी के रूप में दर्शाती नवनीत शर्मा की डायरी।

सप्तरंग

तकनीकी की दुनिया का फर्जी लोन एप बड़े जालमें फंसेने से लक्ष्मण की बताते हैं फोन में लग रही है सेंस

रामलला की आरती में नित्य शामिल हो सकेंगे चार सौ भक्त

अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रामलला के दर्शन के साथ ही उनकी आरती में भी अधिकाधिक श्रद्धालुओं को शामिल करने की योजना बना रहा है। इसका प्रारूप इस तरह बन रहा है, जिससे रामलला की आरती में स्वयं आमलाइन पास बनाकर श्रद्धालु शामिल हो सकें। इसके प्रारूप पर आंतिम विमर्श चल रहा है। अलग-अलग आरती में शामिल होने वालों की संख्या चार सौ तक हो सकती है। ये सभी नित्य होने वाली पांच में से चार आरती में शामिल होंगे।

सोनिया ने छोड़ी रायबरेली, राजस्थान से जाएंगी राज्यसभा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जयपुर में नामांकन के समय सोनिया के साथ थे राहुल और प्रियंका गांधी

कांग्रेस ने सोनिया समेत घोषित किए राज्यसभा चुनाव के 10 प्रत्याशी

अभिषेक सिंधवी हिमाचल व अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार से उम्मीदवार

माकन को कर्नाटक से मोका, रेणुका चौधरी तेलंगाना से कर्गेशी वापसी

मध्य प्रदेश से अशोक सिंह व तेलंगाना से अनिल यादव को मिला मोका



राज्यसभा चुनाव के लिए बुधवार को जयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करती सोनिया गांधी। इस अवसर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तथा अशोक गहलोत भी उपस्थित रहे।

2019 में कर दी थी अगला लोस चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा

सोनिया गांधी पांच बार लोकसभा की सदस्य रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद 1999 में वह पहली बार लोकसभा सदस्य बनी थीं। लेकिन 2019 में उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वह अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। बुधवार को नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने विधानसभा की विपक्षी लाठी में पार्टी के विधायकों से मुलाकात भी की।

सात मंत्रियों को भाजपा का रास टिकट नहीं

नई दिल्ली: राज्यसभा से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल सात मंत्री लोकसभा चुनाव में उतर सकते हैं। इनका कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है और पार्टी ने इन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया है। भाजपा ने राज्यसभा के टिकट में पुराने के बजाय नए चेहरों पर ज्यादा भरोसा किया है।

हिमाचल प्रदेश की एकमात्र सीट के लिए अभिषेक सिंधवी की उम्मीदवारी की घोषणा की गई। पहले दो बार राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले सिंधवी पिछली बार बंगाल से उच्च सदन में चुने गए थे। कपिल सिब्बल के पार्टी छोड़ने जयपुर पहुंचते ही पहली सूची में उनके समेत चार उम्मीदवारों की पहली सूची कांग्रेस की ओर से जारी की गई। इसमें

अशोक चव्हाण के पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस ने महाराष्ट्र की एक सीट से स्थानीय नेता चंद्रकांत हंडेरे को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। दोपहर बाद जारी पार्टी के छह राज्यसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची में मध्य प्रदेश से अशोक सिंह को टिकट देने की घोषणा के बाद हाईकमान के इस फैसले पर सवाल उठाना मुश्किल

केंद्र हर समाधान के लिए तैयार: मुंडा

किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए कृषि मंत्री ने संवाद और सहयोग पर दिया जोर

जेएनएन, नई दिल्ली



पंजाब-हरियाणा सीमा पर बुधवार को भी 'दिल्ली चलो' मार्च को लेकर किसानों का सुरक्षाकर्मियों से टकराव हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसान।

केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं से आम नागरिकों की परेशानियों को कम करने के लिए सहयोग के साथ ही बातचीत करने का आग्रह किया है। कहा कि नए कानून के निर्माण को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जिन पर सरकार किसान संगठनों से चर्चा करना चाहती है। कृषि मंत्री ने किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए संवाद और सहयोग पर जोर दिया। वहीं, किसान नेता तीसरी बार सरकार से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। उनकी सरकार के कई मंत्रियों के साथ गुरुवार को शाम पांच बजे चंडीगढ़ में बैठक होगी।

किसानों ने शंभू बार्डर पर ही लगा लिया मोर्चा

जागरण टीम, दिल्ली

एमएसपी पर कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर निकले किसानों ने हरियाणा सीमा से सटे पंजाब के शंभू बार्डर पर मोर्चा लगा लिया है। किसान नेताओं ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार से बातचीत तक वे आगे नहीं बढ़ेंगे। इससे पूर्व ट्रैक्टर-ट्रालियों से आगे बढ़ रहे किसानों ने बुधवार को दूसरे दिन भी जमकर उपद्रव किया, लेकिन हरियाणा ने अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। इस बीच, भारतीय किसान यूनियन एकता (उग्राहा) ने पंजाब भर में गुरुवार को दोपहर 12 से शाम चार बजे तक रेल ट्रैक जाम करने की घोषणा की है। पंजाब के विभिन्न जिलों से जुटे किसान मंगलवार दोपहर से ही दिल्ली की कूच के लिए हरियाणा सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। बटिंडा से सटे हरियाणा के डबवाली में स्थिति शांत

रही, लेकिन पटियाला से सटे शंभू और संगरूर व जींद के बीच स्थित दाता सिंह बार्डर पर दूसरे दिन भी किसान उपद्रव करते रहे। हरियाणा पुलिस ने उग्र हुए किसानों को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन से आंशु गैस के गोले छोड़े तो किसानों ने पतंग उड़कर ड्रोन को गिराने का प्रयास किया। आंशु गैस के गोले का असर कम करने के लिए वे पानी की बौछार करते रहे। किसान पानी के टैंकर और स्प्रे ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे। गुलेल से पत्थर मारकर भी ड्रोन गिराने का प्रयास किया। कुछ किसानों ने बताया कि ड्रोन गिराने के लिए पहले वे पत्थर मार रहे थे, लेकिन टकराने से टुकड़ों में बंटे पत्थर से उन्हें चोट पहुंच रही थी। इसलिए टेनिस बाल के जरिये ड्रोन को गिराने की कोशिश की है।

दिल्ली की सभी सीमाएं सील: किसानों के प्रवेश को देखते हुए पड़ोसी राज्यों से जुड़ी दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी हैं। हरियाणा से सटे सिंधु और टीकरी बार्डर पर कड़ी निगरानी की जा रही है।

सीईओ के बार-बार तबादलों से भी पिछड़े स्मार्ट सिटी

मनीष तिवारी, नई दिल्ली



क्रियान्वयन की क्वाएं दूर करनी होगी। प्रतीकात्मक

इस साल स्मार्ट सिटी मिशन पूरा करने में जुटे शहरों कार्य मंत्रालय की योजना में शामिल शहरों में बार-बार सीईओ के तबादलों पर चिंतित केंद्र सरकार ने फिर से राज्यों से कहा है कि वे उनके लिए निश्चित कार्यकाल निर्धारित करें। केंद्र सरकार के अनुसार, स्मार्ट सिटी के एक्सपीबी यानी स्पेशल परपज बेहिकल के सीईओ का कार्यकाल कम से कम दो साल का होना चाहिए ताकि वे अपना काम ठीक ढंग से कर सकें। इन एक्सपीबी पर ही शहर स्तर पर योजनाएं बनाते, उनका क्रियान्वयन करने और निगरानी की जिम्मेदारी होती है। इनमें स्थानीय शहरी निकाय और संबंधित राज्य सरकार की आधी-आधी हिस्सेदारी होती है। शहरी कार्य मंत्रालय ने माना है कि स्थानीय परिस्थितियों के कारण सीईओ के बार-बार तबादलों की नौबत आती है, लेकिन यह नहीं होना चाहिए। स्मार्ट सिटी मिशन कई

व्यक्ति हैं कि वहां सीईओ का हर छह महीने या उससे भी कम समय में तबादला हो रहा है। एक तो तबादले जल्दी-जल्दी हो रहे हैं और दूसरे, परिवर्तन की बार-बार बदली जा रही है। इससे काम प्रभावित होता है। सबसे ज्यादा पिछड़े शहरों में शिमला और धर्मशाला जैसे शहर भी हैं। इन सभी की रैंकिंग 80 से नीचे है। मंत्रालय की चिंता यह भी है कि क्रियान्वयन की क्वाएं दूर करनी होगी। प्रतीकात्मक

विस्तार के बाद इस साल जून में पूरा होना है, लेकिन अभी भी काफी परिवर्तनएं लंबित हैं। मिशन के क्रियान्वयन की चुनौतियों में सीईओ के बार-बार तबादलों के मसले को भी शामिल किया गया है। शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित एक संसदीय समिति ने भी इस पर अपनी चिंता जताते हुए मंत्रालय से जवाब जानना चाहा था। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, सीईओ का बार-बार स्थानांतरण सही नहीं है। सबसे पिछड़े शहरों में सबसे बड़ा कारण भी

पाक में एमबीबीएस में दाखिले की आड़ में टेरर फंडिंग में तीन गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

पाकिस्तान में एमबीबीएस में दाखिले की आड़ में टेरर फंडिंग मामले में ईडी ने बुधवार को तीन को गिरफ्तार किया है। सभी जम्मू कश्मीर में आतंकीयों व अलगाववादियों के ईको सिस्टम के अंतर्गत कार्य करने के लिए जिम्मेदार थे। वे सभी अलगाववादी हरियत कांफ्रेंस के पूर्व नेता हैं और इनमें एक महिला भी है। श्रीनगर न्यायालय में विशेष कोर्ट ने तीन आरोपितों को 20 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। अब इस मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार आरोपितों की संख्या चार हो गई है। ये चारों जेल में बंद थे। इस मामले में कुल आठ आरोपित हैं, जिनमें से दो पाकिस्तान में छिपे बैठे हैं और दो पुलिस हिरासत में बताए जा रहे हैं।

सभी हरियत कांफ्रेंस के पूर्व नेता, एक महिला भी, कुल आठ आरोपित, दो पाकिस्तान में छिपे बैठे

दाखिला दिलाने के बदले पसूलते थे मोटी रकम, पैसा घाटी में आतंकी गतिविधियों में लगाते थे

अलगाववादी पाकिस्तान में कश्मीर के छात्र-छात्राओं को एमबीबीएस व इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिला दिलाने और बदले में एक मोटी रकम वसूलकर उसे घाटी में आतंकी व अलगाववादी गतिविधियों में लगाने का काम करते थे। इनका कश्मीर में एक बड़ा नेटवर्क था। इसी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच के आधार पर अब ईडी आगे बढ़ रही है।

वोटिंग स्याही से पांच सेकेंड में ही बनेगा अमिट निशान

नई दिल्ली: चुनावों में अंगुलियों पर लगाने वाली स्याही को अब मिटाना आसान नहीं होगा। बल्कि, यह अंगुलियों पर लगाने के पांच सेकेंड के भीतर ही अपनी छाप निशान बना देगी। अंगुलियों में इसे लगाने से पहले अब यह भी देखा जाएगा कि मतदाता ने अपने हाथों में विकनाई वाली कोई चीज तो नहीं लगाई है।

संदेशखाली घटना की सीबीआई जांच की मांग

कोकता: विपक्ष के नेता सुवेदु अधिकारी ने संदेशखाली घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन और सलाहक दल सुबुत नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट केंद्रीय जांच एजेंसी की महिला अधिकारियों की टीम बनाए और त्वरित कार्रवाई करे।

मणिपुर पीटीसी में घुसने का प्रयास, गोलीबारी में एक की मौत

इंफाल: पूर्वी इंडिया के परोई में मणिपुर पुलिस प्रशिक्षण कालेज (एमपीटीसी) में घुसने का प्रयास करने वाले सशस्त्र युवाओं को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा कर्मियों द्वारा की गया बम में की गई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई।

मंत्रोच्चार के बीच मोदी ने किया अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन



अबुधाबी में बुधवार को वीपीएस हिंदू मंदिर के लोकार्पण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

अबू धाबी, यूएई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मंत्रोच्चार के बीच अबू धाबी के पहले मंदिर का उद्घाटन किया। यह पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर को मानवता की साझा विरासत का प्रतीक बताते हुए प्रधानमंत्री ने मानवता के इतिहास में नया सुनहरा अध्याय लिखने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को धन्यवाद दिया।

दुबई-अबू धाबी श्रेष्ठ जायद राजमार्ग पर अल रहबा के पास अबू मरेखह में 27 एकड़ भूमि पर लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत से इस मंदिर का निर्माण बोचासनासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीपीएस) ने करवाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में भव्य मंदिर के निर्माण को हकीकत में बदलने के लिए यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नाहयान को हार्दिक धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने न सिर्फ खूबी देखा और बने वाले भारतीयों का, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का भी दिल जीत लिया है। यूएई सरकार ने करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरे दिल से काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि बीपीएस मंदिर पूरी दुनिया में सांस्कृतिक सद्भाव और वैश्विक एकता का प्रतीक बनेगा। इस दौरान यूएई के सहयोगी मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान और सभी पंथों के आध्यतिक गुरु उपस्थित थे।

यूएई के राष्ट्रपति को दिया धन्यवाद दिया, कहां-140 करोड़ भारतीयों का जीता दिल

जताई उम्मीद- दुनिया में सांस्कृतिक सद्भाव और वैश्विक एकता का प्रतीक बनेगा मंदिर

राम मंदिर की तरह नागर शैली में हुआ निर्माण

मंदिर के अधिकारियों के अनुसार, भव्य मंदिर का निर्माण शिल्प और स्थापत्य शास्त्रों में वर्णित निर्माण की प्राचीन शैली के अनुसार किया गया है। इसे नागर शैली में बनाया गया है, जिस शैली में अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किया गया है।

यूएई के राष्ट्रपति को दिया धन्यवाद दिया, कहां-140 करोड़ भारतीयों का जीता दिल

मंदिर के अधिकारियों के अनुसार, भव्य मंदिर का निर्माण शिल्प और स्थापत्य शास्त्रों में वर्णित निर्माण की प्राचीन शैली के अनुसार किया गया है। इसे नागर शैली में बनाया गया है, जिस शैली में अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किया गया है।

'मां पर धन और समय खर्च करना घरेलू हिंसा नहीं

मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने कहा है कि पति द्वारा अपनी मां को समय देना और वित्तीय सहायता प्रदान करना घरेलू हिंसा नहीं है। अदालत ने यह फैसला एक 43 वर्षीय एक महिला की याचिका खारिज करते हुए सुनाया जिसमें उसने घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा अधिनियम के तहत अपने पति एवं उसके स्वजन के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी।

बेहमई कांड में 43 साल बाद एक को उग्र कैद, एक बरी

कानपुर देहात: कानपुर देहात के बेहमई गांव में 43 वर्ष पहले हुए नरसंहार पर बुधवार को फैसला आया। घटना में दस्यु रही फूलन देवी समेत 36 आरोपित बनाए गए थे। फूलन देवी समेत 33 आरोपित अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक अपर तक फरार है, वहीं दो लोग जमानत पर चल रहे थे। एक को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है।

आज का मौसम
हल्के से मध्यम श्रेणी का कोहरा होगा।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
15 फरवरी	25.0	09.0
16 फरवरी	25.0	08.0
नोएडा		
15 फरवरी	24.0	08.0
16 फरवरी	25.0	08.0
गुरुग्राम		
15 फरवरी	22.0	09.0
16 फरवरी	22.0	09.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

सीबीएसई परीक्षाएं आज से, 10 बजे तक केंद्र पर पहुंचें छात्र
नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो रही हैं। परीक्षा सुबह 10.30 बजे से शुरू होगी। सभी छात्रों को बोर्ड की ओर से सुबह 10 बजे केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद पहुंचने वाले छात्रों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली में 877 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 5,80,192 छात्र शामिल होंगे। बोर्ड ने जारी निर्देशों में कहा है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के कारण, यह आकांक्षा है कि प्रत्यायत संबंधी समस्याएं होंगी। इसीलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने घरों से जल्दी निकलें। (जास)

अस्पताल में डाक्टर बनकर घुसने वाला गिरफ्तार

नई दिल्ली : डाक्टर बन आरएमएल अस्पताल के सर्जरी विभाग की ड्रमरजेंसी में घुसे एक शास्त्र को नार्थ एवेन्यू पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान वजीराबाद गांव बुराड़ी निवासी 24 वर्षीय आशुतोष त्रिपाठी के रूप में हुई है। बताया गया कि वह चोरी की नीयत से घुसा था। हालांकि सीनियर डाक्टर की नजर उस पर पड़ गई और उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। (जास)

फैक्टरी आफ टेक्नोलॉजी भवन का जल्द होगा निर्माण

नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय में फैक्टरी आफ टेक्नोलॉजी के नए भवन के निर्माण कार्य का शुभारंभ कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने भूमि पूजन के साथ किया। इसके साथ ही फैक्टरी आफ टेक्नोलॉजी के नए भवन का कांस्ट्रक्शन 14 फरवरी को शुरू हो गया। कुलपति ने बताया कि अगले 5.41 दिनों में इसके निर्माण कार्य को संपूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। 16 अगस्त 2025 तक यह भवन बन कर तैयार हो जाएगा। इस शैक्षणिक भवन का निर्माण कार्य एनबीसीसी (बीडिया) लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। (जास)

अर्बन एक्सटेंशन रोड दो के लिए जमीन अधिग्रहण की मंजूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

एलजी वीके सक्सेना ने काफी समय से लंबित अर्बन एक्सटेंशन रोड (यूईआर दो) के लिए जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इस आशय की जानकारी बुधवार को राजनिवास अधिकारियों ने दी। यूईआर-दो को प्लानिंग एक बाईपास के जरिये उत्तर एवं दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के बीच भीड़ कम करने के लिए की गई है। एलजी ने भरथाल गांव में दो बीघा जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण करना काफी अहम था। रिफर्न इस जमीन का अधिग्रहण नहीं होने की वजह से प्रोजेक्ट को पूरा करने में सात साल की देरी हुई। अप्रैल 2016 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के भरथाल गांव में जमीन अधिग्रहण को लेकर अग्रह किया था, लेकिन कई मुश्किलों की वजह से इस जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सका था। यूईआर दिल्ली मास्टर प्लान में प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट को

ई-बसें लाने का मकसद दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाना : एलजी

बढ़ी सुविधा ▶ उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री ने 350 नई इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी

सीएम केजरीवाल बोले, देश में सबसे अधिक ई-बसें चलाने वाला पहला राज्य बना दिल्ली

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने राज्य की सड़कों पर बुधवार को 350 और नई इलेक्ट्रिक बसें उतार दीं। इन्हें मिलाकर अब राजधानी में 1650 इलेक्ट्रिक बसें हो गई हैं। सरकार ने दावा किया कि अब सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बसों के मामले में दिल्ली भारत का पहला और विश्व का तीसरा शहर बन गया है, जबकि दो हजार ई-बसों के बड़े के साथ चिली को राजधानी सैंटियागो दुनिया का दूसरा शहर है, जबकि पहले बसें सुखदेव विहार, रोहिणी सेक्टर-37 डिपो-वे और बुराड़ी बस डिपो-एक से अलग-अलग रूटों पर चलानी शुरू हो गई हैं।

सभी लो-फ्लोर ई-बसें हैं। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ये बसें जीपीएस, सीसीटीवी, पैनिक बटन समेत अन्य



सुविधाओं से लैस हैं। दिल्ली के सराय काले खां बस डिपो में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान एलजी वीके सक्सेना के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल ने नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और बसें में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि ई-बसों को लाने का मकसद दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाना है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ई-बस चलाने में दिल्ली दुनिया में अपनी पहचान

1300 इलेक्ट्रिक बसों से 47 हजार टन कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन कम होने का दावा

ई-बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते एलजी वीके सक्सेना, सीएम अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत। चंद्र प्रकाश मिश्र

बना रही है। हमें खुशी है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बस चलाने के मामले में देश में दिल्ली पहला राज्य बन गया है। ये ई-बसें न सिर्फ दिल्लीवासियों का सफर आसान बनाएंगी, बल्कि पर्यावरण को संतुलित रखने में भी सहायक होंगी। दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने में प्रत्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ई-बस चलाने में दिल्ली दुनिया में अपनी पहचान

केजरीवाल को आबकारी मामले में ईडी का छटा समन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लाँड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को फिर से समन जारी किया है। यह छटा समन है। उन्हें 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया है।

पिछले पांच समन की अवज्ञा करने पर ईडी की ओर से दायर शिकायत पर कोउर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को उसके समक्ष 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था। अदालत ने कहा था कि केजरीवाल प्रथमदृष्टया समन का अनुपालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। इससे पहले ईडी ने इस वक में 18 जनवरी और 18 जनवरी और पिछले वर्ष 21 दिसंबर एवं दिसंबर को मुख्यमंत्री को समन जारी किया था। मुख्यमंत्री हर बार ईडी के समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते रहे और एजेंसी के सामने कभी पेश नहीं हुए।



आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए 19 फरवरी को बुलाया

बता दें कि आबकारी घोटाले के मामले में ईडी की ओर से दायर आरोपपत्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है। आरोपित दिल्ली राजज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को उसके समक्ष 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था। अदालत ने कहा था कि केजरीवाल प्रथमदृष्टया समन का अनुपालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। इससे पहले ईडी ने इस वक में 18 जनवरी और 18 जनवरी और पिछले वर्ष 21 दिसंबर एवं दिसंबर को मुख्यमंत्री को समन जारी किया था। मुख्यमंत्री हर बार ईडी के समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते रहे और एजेंसी के सामने कभी पेश नहीं हुए।

जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली जमानत अर्जी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

नई दिल्ली, प्रे: दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली। फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने के आरोप में खालिद पर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद खालिद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस पंकेज मिश्र को पीठ से खालिद की ओर से पेशा वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण खालिद अपनी जमानत अर्जी वापस लेना चाहता है और अब हम ट्रायल कोर्ट जाना चाहते हैं। पीठ ने सिब्बल का अनुरोध स्वीकार कर खालिद को जमानत अर्जी वापस लेने का आदेश दिया। खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट के 18 अक्टूबर 2022 को दिए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

घटिया चिकित्सा उपकरण आपूर्ति करने वाले दस गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार के छह अस्पतालों में खराब गुणवत्ता के चिकित्सा उपकरण आपूर्ति करने के मामले में बड़े स्तर के फर्जीबाड़े का भंडाफोड़ किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने सात उपकरण निर्माताओं व सप्लायर्स और तीन प्रयोगशाला प्रबंधकों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि जिन कंपनियों ने अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण आपूर्ति किए, उनमें से कई के पास उपकरणों के निर्माण करने का लाइसेंस ही नहीं था। साथ ही चिकित्सा उपकरणों सप्लायर होने के बाद कर दिए गए, जबकि इनकी खरीद की स्विकृति बाद में मिली। दिल्ली सरकार के लोक नायक, एलबीएस, डीडीयू, एसजीएम, जेएसएस और जीटीबी अस्पताल में इन खराब गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की गई थी। संयुक्त आयुक्त एसीबी मधुर वर्मा ने बताया कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की शिकायत के बाद पांच जनवरी को इस मामले में एफआइआर दर्ज की गई थी। अब एसीबी इस फर्जीबाड़े में शामिल

- छह सरकारी अस्पतालों में खराब चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति का भंडाफोड़
- सात उपकरण निर्माता व सप्लायर्स और तीन प्रयोगशाला प्रबंधकों को पकड़ा गया
- कई कंपनियों के पास चिकित्सा उपकरणों का निर्माण करने का नहीं था लाइसेंस



एसीबी द्वारा गिरफ्तार आरोपित। सौजन्य : दिल्ली पुलिस

चिकित्सा उपकरण खरीदने वाली कमेटी के डाक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। एसीबी ने अब इस मामले में डीडीयू और एलएनजेपी अस्पताल के नौ डाक्टरों के खिलाफ भी एफआइआर दर्ज करने की सफाई से अनुमति मांगी है। एसीबी जर्नेल सिंह का कहना है कि इस मामले में आरोपितों से पूछताछ के बाद अन्य अस्पतालों के डाक्टरों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

इन आरोपितों को किया गया गिरफ्तार : गिरफ्तार आरोपितों में हेमंत जोशी (बाल

बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली व सड़कों पर फोकस की संभावना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत गुरुवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अधिभाषण से होगी। सत्र के पहले दिन बिजनेस एडवाइजरी समिति की छठी रिपोर्ट पेश की जाएगी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोक लेखा, अनुमान और सरकारी उपक्रमों पर सदन समितियों में से प्रत्येक में नौ सदस्यों को चुनने के लिए एक प्रस्ताव पेश करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सड़कों समेत अन्य पर फोकस रहने की संभावना है। बताया गया कि बजट में बिजली विभाग को 3600 करोड़, गांवों के विकास के लिए 900 करोड़, लोक निर्माण विभाग को 7700 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। इस बार जल बोर्ड का बजट भी बढ़ सकता है। वहीं, दिल्ली सरकार की ओर पहले से दी जा रही मुफ्त की योजनाएं जारी रहने की संभावना है।

आम आदमी पार्टी की ओर से आबकारी नीति से जुड़े मनी लाँड्रिंग मामले में केजरीवाल को बार-बार समन भेजे जाने का मुद्दा उठाए जाने की संभावना है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मामले में पूछताछ के लिए उन्हें छटा समन भेजा। आप ने बार-बार आरोप लगाया है कि कई समन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप को कुचलने और दिल्ली में सरकार गिराने का एक प्रयास है। दिल्ली विधानसभा

विधानसभा का बजट सत्र आज से



बजट सत्र पर टीकी निगाह।

पीएम मोदी का आभार जताने को भाजपा जाएगी प्रस्ताव

अधिकारियों ने बताया कि सरकार सत्र के दौरान अपना अउटकम बजट भी दिल्ली की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश करेगी। विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिबूड़ी ने कहा कि पूर्व पीएम नरसिंहा राव और पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी समेत दिग्गजों को भारत रत्न देने और कतर में मीत की सजा पाए नौ भारतीयों की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए भाजपा एक प्रस्ताव लाएगी। अस्पताल की स्थिति, प्रदूषण जैसे मुद्दों पर सवाल पूछने की कोशिश होगी।

के बजट सत्र में वित्त मंत्री आतिश्री द्वारा 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा, जो 15 फरवरी से शुरू होकर 21 फरवरी को समाप्त होगा।

विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं ने जोईएम पोर्टल के माध्यम से इन उपकरणों की आपूर्ति की थी। नियमानुसार उपकरणों की आपूर्ति के साथ ही सरकार की ओर से मांगे गए अनिवार्य प्रमाणपत्र भी देने थे। जिसमें प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी शामिल है, लेकिन जांच में सामने आया कि सरकारी अधिकारी जानबूझकर जोईएम अनुबंध आदेश में लैब रिपोर्ट और आपूर्तिकर्ताओं के लाइसेंस लेने से बचते रहे। कुछ मामलों में न तो आपूर्तिकर्ता का लाइसेंस नंबर था, न ही निर्माता का। अधिकांश मामलों में वितरित उपकरण की बैच संख्या निर्माता और आपूर्तिकर्ता के बैच संख्या से मेल नहीं खा रही थी।

स्थानीय बाजारों से वरिष्ठ अमानक उपकरण खरीदकर आपूर्ति : जांच में सामने आया कि स्थानीय बाजारों से बगैर मानकों के खराब गुणवत्ता के उपकरण खरीदकर सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति की गई। एसपी जर्नेल सिंह का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अधिकारी और आपूर्तिकर्ता दस्तावेज में जालसाजी करते रहे। मुकदमा दर्ज होने से पहले विजिलेंस जांच कराने पर उपकरणों के नमूने 18 अगस्त को लिए गए थे।

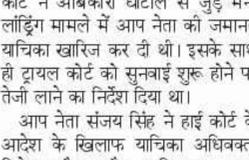
आबकारी नीति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे संजय सिंह

नई दिल्ली, प्रे: आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गत सात जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लाँड्रिंग मामले में आप नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट को सुनवाई शुरू होने पर तेजी लाने का निर्देश दिया था। आप नेता संजय सिंह ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका अधिवक्ता विवेक जैन और अधिवक्ता रजत भारद्वाज के माध्यम से दखिल की। संजय सिंह को गत चार अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने हाई कोर्ट से इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह तीन माह से अधिक समय से हिरासत में हैं और दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार से जुड़े अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है। जांच एजेंसी ने कोर्ट में उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था। ईडी ने हाई कोर्ट में दावा किया था कि सिंह घोटाले में प्रमुख साजिशकर्ता हैं।

'आयुष्मान भारत' के तहत एम्स में 5179 कैसर रोगियों का उपचार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन के बाद से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने आन्कोलाजी केंद्र में 5,179 कैसर रोगियों का उपचार किया है। साथ ही 148 घुटनों के रिप्लेसमेंट किए गए हैं। इन वर्षों में 23,260 मरीजों को योजना का लाभ दिया गया है। एम्स में आयुष्मान भारत योजना के प्रभारी प्रोफेसर डा. वीके बंसल ने बताया कि 27 स्पेशियलिटी केंद्रों में 1109 पैकेज में 1949 प्रक्रियाएं प्रदान की जा रही हैं। इनमें शीशं पांच स्पेशियलिटी केंद्रों आन्कोलाजी के अलावा नेत्र विज्ञान विभाग में 4275 मरीजों का, जनरल मेडिसिन में 3169, आर्थोपेडिक्स में 2260 और न्यूरोसर्जरी में 2223 मरीजों को उपचार दिया गया है। आयुष्मान



बढ़ रही यमुना की दुर्दशा। प्रतीकात्मक

राजधानी में यमुना के हिस्से में 23 क्यूमेक्स जल प्रवाह कम : डीपीसीसी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने कहा है कि यमुना नदी के राष्ट्रीय राजधानी में पड़ने वाले हिस्से में जल प्रवाह 23 घन मीटर प्रति सेकेंड (क्यूमेक्स) कम है। यह जल प्रवाह स्नान योग्य होने और नदी में पारिस्थितिकी बरकरार रखने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। अलबत्ता, डीपीसीसी का यह कहना पिछले सप्ताह एक संसदीय समिति द्वारा की गई उस सिफारिश से मेल नहीं खाता है, जिसने दिल्ली में यमुना के 22 किमी लंबे हिस्से में 23 घन मीटर प्रति सेकेंड (क्यूमेक्स) 'ई-फ्लो' रखे जाने की बात कही है। गौरतलब है कि दिल्ली में पड़ने वाला नदी का हिस्सा इसके करीब 80 प्रतिशत प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। ई-फ्लो (जल प्रवाह) की न्यूनतम मात्रा है, जिसे किसी नदी को अपनी पारिस्थितिकी बरकरार रखने और उसके स्नान योग्य होने के लिए जरूरी है। राष्ट्रीय जल

- रिपोर्ट में कहा, नदी में जल प्रवाह स्नान योग्य होने और पारिस्थितिकी बरकरार रखने के लिए भी पर्याप्त नहीं
- दिल्ली में पड़ने वाला नदी का हिस्सा इसके करीब 80% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार



बढ़ रही यमुना की दुर्दशा। प्रतीकात्मक

आयोजन

800 वर्षों से दरगाह में मनाया जा रहा है वसंत उत्सव, हिंदू मुस्लिम सभी हुए शामिल, गंदे और सरसों के फूलों की दरगाह ने ओढ़ी थी चादर, कत्वाली में बर से वसंत के नज्म

महबूब इलाही निजामुद्दीन की दरगाह खास वासंती रंग ओढ़े हुई थी। पीली चादर के साथ पीले सरसों व गंदे के फूल निजामुद्दीन दरगाह के हर कोने को पीलापन और विशेष खूबाई दिए हुए थे। कत्वाली में भी महाशूर शायर अमीर खुसरो के वसंत पर लिखे नज्मों की वर्षा हो रही थी। मौका भी खास था, बुधवार शाम यहां धूमधाम और परंपरागत तरीके से वसंतोत्सव मनाया गया। इसमें हजारों लोग पीले परिधान और पीले साफे के साथ हाथ में पीले फूल लिए शामिल हुए। इसके लिए दरगाह में विशेष तैयारियों की गई थीं। दरगाह को विशेष पीले लाइटों से सजया गया था। हर ओर पीले गंदे और सरसों के फूलों की महक थी। बैसै यह कोई पहली बार नहीं है। गंगा-यमुना तहजीब को प्रगाढ़ करने की यह अनूठी परंपरा 800 से अधिक वर्षों से चली आ रही है। जब यह दरगाह हिंदू धर्म के विशेष उत्सव को

वसंत उत्सव की अनूठी परंपरा से महकी निजामुद्दीन दरगाह

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली



निजामुद्दीन दरगाह में लगभग 800 वर्षों से वसंत उत्सव मने की परंपरा के तहत बुधवार को पीले पत्र में सरसों के फूलों से होली खेलते हुए हिंदुओं और मुस्लिमों के सौहार्द का दृश्य देखने को मिला। चंद्र प्रकाश मिश्र

आत्मसात करता है। विशेष बात कि इस उत्सव में शामिल होने के लिए हर धर्म के लोग शामिल हुए। विदेशी

पर्यटक भी इसे देखने के लिए विशेष तौर पर पहुंचे। इसमें कई विशिष्ट लोग भी शामिल थे।

सभी को चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त सरकार : पीएम मोदी

दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट्स सभित में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन

बोले- दुनिया में सरकारों पर कम हुआ भरोसा, भारत में बढ़ा जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली



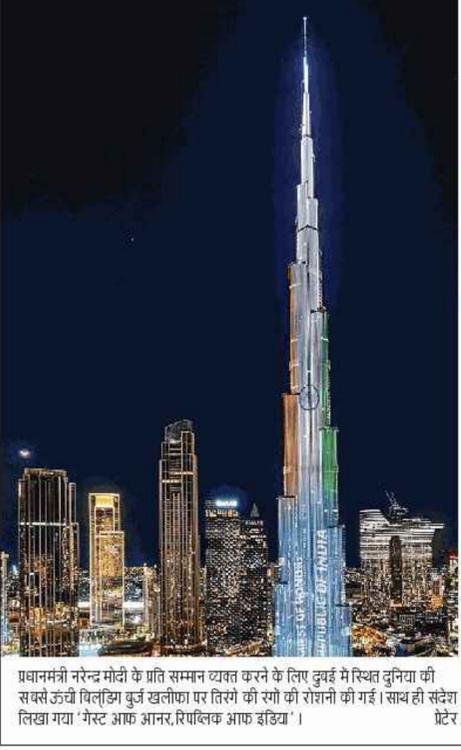
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट्स सभित को संबोधित किया। एएफपी

दुनिया में ऐसी सरकारों की जरूरत है जो स्वच्छ हो, पारदर्शी हो, भ्रष्टाचार से दूर हो और सभी को साथ लेकर चले। यह बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट्स सभित को संबोधित करते हुए कही। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की दो दिवसीय यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को इस वैश्विक कार्यक्रम में कई देशों के नेताओं के सामने न सिर्फ अपनी सरकार की कार्यशैली और नीतियों को विस्तार से गिनया बल्कि यह भी बताया की कोशिश की कि क्यों भारत की जनता का उनका सरकार के प्रति भरोसा बढ़ता जा रहा है। इस क्रम में प्रधानमंत्री ने भौगोलिक अखंडता की सुरक्षा करने और सभी देशों को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की हिदायत देकर चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद की तरफ भी इशारा कर दिया। यह सम्मेलन हर साल दुबई में आयोजित होता है जो सरकारों को भविष्य की चुनौतियों और इनके लिए अनुभव साझा करने का एक प्रसिद्ध प्लेटफार्म बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'कई विश्वेशों का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद

सरकारों के प्रति आम जनता का भरोसा कम हुआ है। लेकिन भारत में हमने एकदम विपरीत अनुभव देखा है। बीते वर्षों में भारत सरकार पर देश के लोगों को हमारी सरकार की प्रतिबद्धता पर भरोसा बढ़ा है। क्योंकि हम देशवासियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हैं। लोगों की जरूरतों और सपने दोनों को पूरा करने पर ध्यान दिया है। 23 वर्षों में सरकार में मेरा सबसे बड़ा सिद्धांत यह रहा है कि न्यूनतम गवर्नमेंट, अधिकतम गवर्नेंस।' समद रहे कि हाल ही में भारत में पांच राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं जिसमें तीन राज्यों (राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) में भाजपा को विजय हासिल हुई है। इसमें तो राज्य उसने कांग्रेस से हासिल किए हैं। मोदी ने वैश्विक नेताओं को चेताया,

'पिछली सदी से खाद्य, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसी चुनौतियों का अब विस्तार हो रहा है। अतर्कवाद एक नए स्वरूप के साथ मानवता के सामने नई चुनौती लेकर आ रहा है, जबकि पर्यावरण संबंधी चुनौतियां बड़ी होती जा रही हैं। इन चिंताओं के बीच अंतरराष्ट्रीय सिस्टम बिखरा नजर आ रहा है। सरकारों के सामने अपनी प्रासंगिकता को बचाना भी चुनौती है। ऐसे में विश्व को ऐसी सरकार चाहिए जो पर्यावरण सुरक्षा को लेकर गंभीर हो, सभी को साथ लेकर चले, स्मार्ट हो, प्रौद्योगिकी को बढ़े बदलाव का जरिया बनाए।'

बतौर प्रधानमंत्री विगत 10 वर्षों जो अहम बदलाव उन्होंने किए हैं, उसके बारे में मोदी ने बताया कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। 400 अरब डॉलर से ज्यादा की राशि संधे लोगों के बैंक खाते में डाली गई है। इससे भ्रष्टाचार की संभावना को खत्म किया गया है और 33 करोड़ डॉलर की राशि गलत हाथों में जाने से रोकी गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थानों में बदलाव की मांग भी इस मंच पर रखी। कहा कि जब हर देश अपने आप में बदलाव कर रहे हैं तो वैश्विक संस्थानों में भी सुधार होने चाहिए। हमें भविष्य की योजना बनानी है, विकासशील देशों की भागीदारी सुनिश्चित करनी है।



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची विलडिगि बर्ज खलीफा पर तिरंगों की रंगी रोशनी की गई। साथ ही संदेश लिखा गया 'मेस्ट आफ आनर, रिपब्लिक आफ इंडिया'। ग्रेटर

मोदी के स्वागत में तिरंगे के रंगों से जगमगाया बर्ज खलीफा

दुबई, ग्रेटर : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की बातचीत के दौरान मंगलवार को दुबई का प्रसिद्ध बर्ज खलीफा तिरंगे के रंगों से जगमगा उठा। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने मंगलवार को बर्ज खलीफा की दो तस्वीरें साझा कीं। इसमें बर्ज खलीफा भारतीय ध्वज के रंगों और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के लोगो से जगमगा रही थी। भारत इस वर्ष दुबई में आयोजित विश्व सरकार सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुआ है। दुबई के क्राउन प्रिंस ने एक्स पोस्ट में तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि हम इस वर्ष के विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के सम्मानित अतिथि भारत गणराज्य और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे देशों के बीच मजबूत संबंध अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए माडल के रूप में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व सरकार सम्मेलन शासन के सर्वोत्तम तरीकों, सफलता की कहानियों और पहलों को साझा करने के लिए दुनिया के अग्रणी प्लेटफार्मों में से एक है। इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल करना हमारे लिए खुशी की बात है।

कोर्ट को मध्यस्थता वाले फैसलों को बदलने की शक्ति देने की सिफारिश

नई दिल्ली, ग्रेटर : पूर्व विधि सचिव टीके विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति ने मध्यस्थता क्षेत्र में सुधारों पर अपनी रिपोर्ट कानून मंत्रालय को सौंप दी है। समिति ने मध्यस्थता कानून में संशोधन की सिफारिश की है ताकि अदालत को मध्यस्थता संबंधी फैसलों को टरकिकार करने या बदलने की शक्ति प्रदान की जा सके। विधि जगत के प्रतिनिधियों ने कानून में प्रस्तावित बदलावों को देश में मध्यस्थता संबंधी सुधारों के लिए झटका बताया है।

पूर्व कानून सचिव टीके विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली समिति ने मध्यस्थता सुधारों पर सौंपी रिपोर्ट

सरकार ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति का किया था गठन

बाले मध्यस्थता संबंधी निर्णयों की संख्या पर भी कोई सीमा तय नहीं की गई है। उन्होंने इस बात पर भी गौर किया कि मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। समिति को मध्यस्थता अधिनियम की कार्यप्रणाली समेत देश के वर्तमान मध्यस्थता पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन के बावत आकलन और उसका विश्लेषण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक टीनाम अपील पर सुनवाई करते हुए कहा था कि समिति की रिपोर्ट का एक मसौदा सरकार को मिल गया है। इसलिए रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद उसकी प्रति दी जानी चाहिए।

अयोध्या की असीम खुशी अबू धाबी में और बढ़ गई : मोदी

प्रथम पृष्ठ से आगे

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएंगे। इससे यूएई आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और वेतन देशों के बीच लोगों का आपसी संपर्क भी बढ़ेगा।' प्रधानमंत्री ने पिछले महीने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भी याद किया। उन्होंने कहा, 'अयोध्या की हमारी असीम खुशी आज अबू धाबी में मिली खुशी की लहर से और बढ़ गई है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं पहले अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर और फिर अबू धाबी में इस मंदिर का साक्षी बना हूँ। अभी पिछले महीने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सदियों पुराना सपना पूरा हुआ। रामलला अपने भवन में विराजमान हैं। पूरा भारत और हर भारतीय अभी भी उस प्रेम की भावना में डूबा हुआ है।' मोदी ने कहा कि यह केवल भारत का 'अमृत काल' नहीं है, यह हमारी आस्था और संस्कृति के 'अमृत काल' का भी समय है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर



अबू धाबी में कुव्वार को बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के नवनिर्मित हिंदू मंदिर के लोकार्पण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं अन्य। ग्रेटर

के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। मंदिर में वज्रुअल गंगा और यमुना नदियों में जल चढ़ाया। साथ ही मंदिर में हथौड़े और छेनी का उपयोग करके पत्थर पर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' भी अंकित किया। उन्होंने 'वैश्विक आरती' में भी

भाग लिया, जो द्वारा दुनियाभर में निर्मित स्वामीनारायण संप्रदाय के 1,200 से अधिक मंदिरों में एक साथ की गई। **कारिगरी से की मुलाकात** : मंदिर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर का निर्माण करने वाले कारिगरी से

मुलाकात की। गुजरात और राजस्थान प्रबंधक मधुसूदन पटेल ने बताया, 'हमने निर्माण में योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने शुरुआत से लेकर पूरा होने तक मंदिर निर्माण में शामिल रहे स्वयंसेवकों एवं इसमें काम में योगदान देने वाले प्रमुख लोगों से भी भेंट की।

हर लेवल पर 300 से अधिक सेंसर : बीपीपीएस के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख स्वामी ब्रह्मविहारिदास ने बताया, 'मंदिर में वास्तुशिल्प पद्धतियों के साथ ही वैज्ञानिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया है। तापमान, दबाव एवं गति (भूकंपीय गतिविधि) मापने के लिए मंदिर के हर लेवल पर 300 से अधिक हाई-टेक सेंसर लगाए गए हैं। ये सेंसर उपलब्ध कराएंगे। अगर इस क्षेत्र में कोई भूकंप आता है तो मंदिर इसका पता लगा लेगा और हम उसका अध्ययन कर पाएंगे।'

नई हवा धातु का उपयोग : मंदिर निर्माण में किसी धातु का उपयोग नहीं किया गया है और काबन फुटप्रिंट घटाने के लिए नॉव भरने में रख (प्लाई एश) का

भारत और यूएई में सहयोग बढ़ाने को दस समझौते

अबू धाबी, ग्रेटर : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यूएई दौरे में दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के दस समझौते किए हैं। जिन क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौते हुए हैं उनमें ऊर्जा, आधारभूत ढांचा, निवेश और प्रबंधन शामिल हैं। इन समझौतों से दोनों देशों के संबंधों में और ज्यादा मजबूती आएगी। समझौतों की जानकारी देते हुए यह बात भारतीय विदेश सचिव विनय कवात्रा ने कही है। अबू धाबी में प्रेस कांफ्रेंस में कवात्रा ने कहा, भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय कारोबार 85 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है। इतना ही नहीं यूएई भारत में सबसे ज्यादा निवेश करना वाला चौथा देश है। हमारे संबंधों का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मुहम्मद बिन जायद ने मंगलवार को हवाई अड्डे पर आकर समारोहपूर्वक प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया था। इसके बाद दोनों नेताओं ने आपस में बात की और उसके बाद प्रतिनिधिमंडलों के जरिये बात हुई। विदेश सचिव ने बताया कि जो समझौते हुए हैं उनसे भारत में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी और दोनों देशों के बीच ग्रीन हाइड्रोजन के बंधारण का भी समझौता हुआ है। दोनों देश ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए शोध के साथ ही भारत-मध्य पूर्व-यूरोप इकोनोमिक कारिडोर के विकास के लिए भी सहयोग करेंगे। दोनों देश मिलकर आगुति व्यवस्था को भी सुदृढ़ करेंगे जिससे उद्योगों का लागत मूल्य कम होगा और वस्तुएं जल्द उपलब्ध होंगी।

कोविन्द समिति ने एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर अर्थशास्त्रियों संग किया मंथन

नई दिल्ली, ग्रेटर : 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर गठित पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने बुधवार को समिति सदस्य और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह द्वारा लिखे शोधपत्र पर अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा की। सिंह और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के सिस्टमिक डिजिटीशन से संबंधित मुद्दों की प्रमुख प्राची मिश्रा ने 'मैक्रोइकोनॉमिक इंपैक्ट आफ हार्मोनाइजिंग इलेक्ट्रॉनल साइकलस' शीर्षक से शोधपत्र लिखा है। इसे उच्चस्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष के शोधपत्र पर मांगे सुझाव

ओपेसी और गुजरात के चुनाव आयुक्त से की भी चर्चा

शोधपत्र के अनुसार, देश में अलग-अलग चुनाव कराने से खर्च के अलावा व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ता है। कोविन्द समिति ने शोधपत्र पर व्यापक चर्चा की जरूरत बताते हुए मंथन सत्र में अर्थशास्त्रियों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित कीं। बैठक में आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक प्रो. चेतन घाटे, भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के निदेशक और मुख्य कार्यकारी डा. वैपक मिश्रा, अतिवासी

मानद प्रतिष्ठित फेलो, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान के प्रो. इंदिरा राजासमन ने भाग लिया। समिति ने आल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन औबैसी के साथ भी चर्चा की। औबैसी ने एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर समिति के समक्ष पार्षी के विचार रखे। राज्य

चुनाव आयुक्तों के साथ विमर्श जारी रखते हुए समिति ने गुजरात के चुनाव आयुक्त संजय प्रसाद से मुलाकात की। प्रसाद ने विधानसभाओं और लोकसभा के साथ-साथ स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए आवश्यक विभिन्न ताकिक और विधायी आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला।

एआइएमएआइएम के प्रमुख असदुद्दीन औबैसी ने एक राष्ट्र एक चुनाव मुद्दे पर समिति के अध्यक्ष राम नाथ कोविन्द से कुव्वार को मुलाकात कर उन्हें अपनी पक्षी की राय से अगत कराया। एएनआइ

हाई कोर्ट के तीन जजों के स्थानांतरण की सिफारिश

नई दिल्ली, ग्रेटर : चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने विभिन्न हाई कोर्ट के तीन जजों के स्थानांतरण की सिफारिश की है। जजों ने अपने स्थानांतरण का अनुरोध किया था। कलेजियम में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सुब्रत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस भी शामिल थे। कलेजियम ने मंगलवार की बैठक में कहा कि गत 12 फरवरी को जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने व्यक्तिगत कारणों से कलकत्ता हाई कोर्ट से किसी अन्य हाई कोर्ट में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया था। जस्टिस भट्टाचार्य के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हे तेलंगाना हाई कोर्ट में स्थानांतरित किए जाने की सिफारिश की जाती है। कलेजियम ने जस्टिस अनु शिवरामन का अनुरोध स्वीकार कर उन्हे कर्नाटक हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की। उन्हेने केरल राज्य से बाहर स्थानांतरण की मांग की थी। वहीं कलेजियम ने जस्टिस सुजय पाल का अनुरोध भी स्वीकार उन्हे तेलंगाना हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की है। जस्टिस सुजय ने बेटे द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वकालत करने को आदेश बताते हुए स्थानांतरण की मांग की थी।

विचारण न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय न कहा जाए : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सत्र न्यायालय अथवा विचारण न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) को लोअर कोर्ट या अधीनस्थ अदालत कहने का चलन उचित नहीं है। न्यायालय ने महानिबंधक को निर्देश दिया कि इस संबंध में परिपत्र जारी कर हाई कोर्ट रजिस्ट्री कार्यालय को निर्देशित करें कि सेशन कोर्ट के संबंध में लोअर कोर्ट की बजाय ट्रायल कोर्ट का संबोधन प्रयोग में लाएं। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने मेष्ठ के शमशाद अली की अपराधिक पुनरीक्षण अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। मेष्ठ से संबंधित एक प्रकरण में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने रजिस्ट्री को 27 अक्टूबर, 2023 को निर्देश दिया था कि संबंधित ट्रायल कोर्ट का रिपोर्ट मंगया जाए। संबंधित कार्यालय (रजिस्ट्री) की 10 दिसंबर, 2023 की रिपोर्ट में कहा गया कि लोअर कोर्ट का रिपोर्ट अब तक नहीं आया है। इसके बाद कोर्ट ने आफिस को रिमाइंडर भेजने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई से पूर्व 12 फरवरी को कार्यालय ने रिपोर्ट में

महानिबंधक को निर्देश दिया कि लोअर कोर्ट का रिपोर्ट मंगया जाए



इलाहाबाद हाई कोर्ट की अहम व्यपस्था।

कहा कि लोअर कोर्ट का रिमाइंड आ गया है। कोर्ट ने कहा, दो बार जब कार्यालय को ट्रायल कोर्ट का रिपोर्ट मंगाने का निर्देश दिया तो दोनों बार कार्यालय की रिपोर्ट में ट्रायल कोर्ट को लोअर कोर्ट कह कर संबोधित किया गया। ट्रायल कोर्ट को लोअर कोर्ट या अधीनस्थ अदालत के रूप में संबोधित करना उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा, सत्र न्यायालय में दखिल किसी भी मामले, अपील, रिवीजन आदि की पहचान जानना संभव है, जबकि विपक्षी जजों को ऐसी जानकारी नहीं मिल सकती।

चुनावी शुचिता

चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को रोकने के लिए स्याही की गुणवत्ता में किया गया सुधार, वोटर के हाथों में चिकनाई होने पर पहले किया जाएगा साफ

वोटिंग स्याही से पांच सेकेंड में ही बनेगा अमित निशान

अरविंद गांधेय, नई दिल्ली

चुनावों में मतदाताओं की अंगुलियों पर लगने वाली स्याही को मिटाना अब आसान नहीं होगा। यह अंगुलियों पर लगने के पांच सेकेंड के भीतर ही अमित छाप छोड़ देगी। इतना ही नहीं, अंगुलियों पर इसे लगाने से पहले अब यह भी देखा जाएगा कि मतदाता ने अपने हाथों में तेल या फिर चिकनाई वाली कोई चीज तो नहीं लगाई है। यदि ऐसा है तो पहले उसकी अंगुलियों को कपड़े से साफ किया जाएगा। फिर उसे लगाया जाएगा। यही वजह है कि चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों को दी जाने वाली चुनाव सामग्री की किट में अब हाथों को साफ करने के लिए एक कपड़ा भी मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने यह पहल तब की है, जब चुनाव में गड़बड़ी करने वाले लोग पहचान को छुपाने और फिर से वोट डालने के लिए हाथों में लगने वाली स्याही को तुरंत बाद मिटा देते थे। यह इसलिए भी हो जाता था, क्योंकि उनके हाथों में लगने वाली स्याही को



आसान नहीं होगा निशान मिटाना। प्रतीकात्मक

अपनी छाप छोड़ने में थोड़ा वक्त लगता था। चुनाव आयोग ने इस चुनौती को समझा और इससे निपटने के लिए विशेष स्याही बनाने वाली मैसूर (कर्नाटक) के कंपनी से संपर्क किया। इसके बाद इसमें बदलाव किया गया है। इसके चलते अब यह स्याही दो सेकेंड में ही काम शुरू कर देगी। गौरतलब है कि आम चुनाव में विशेष स्याही का इस्तेमाल पहली बार 1962 में किया गया था। इसके बाद तो देश में होने वाले प्रत्येक आम चुनावों में इसका इस्तेमाल होते आ रहा है। अब तो पंचायत सहित दूसरे सभी चुनावों में इस स्याही का इस्तेमाल होता

है। खास बात यह है कि इस स्याही को बनाने का फार्मूला नई दिल्ली स्थित सीएसआइआर की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने खोजा था। बाद में इसे बड़े स्तर पर तैयार करने का लाइसेंस कर्नाटक स्थित मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड (एमपीवीएल) को दिया गया, जो देश में इसे बनाने वाली एकमात्र कंपनी है। साथ ही इसका फार्मूला भी इसी कंपनी के पास है। **कई देश उपयोग के लिए भारत से लेते हैं यह स्याही** : चुनाव में इस्तेमाल होने वाली इस स्याही को लोकप्रियता सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के 30 देशों में भी चुनाव के दौरान इसका इस्तेमाल होता है। जो इसे बनाने वाली कर्नाटक स्थित एक मात्र कंपनी मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड (एमपीवीएल) से मंगाई जाती है। इनमें प्रमुख रूप से मलेशिया, कनाडा, कंबोडिया, घाना, अफगानिस्तान, आइवरी कोस्ट, तुर्किये, नाइजीरिया, पुपुआ न्यूगिनी, नेपाल, सिंगापुर, दुबई, मंगोलिया, दक्षिण अफ्रीका, डेनमार्क आदि देश शामिल हैं।

कह कर रहेंगे माघव जोशी



न्यूज गैलरी

बंगाल की मुख्यमंत्री को आक्सफोर्ड से न्योता
कोलकाता: बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दो प्रमुख विदेशी शिक्षा संस्थानों से न्योता मिला है। उन्हें लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया गया है। ममता ने एक कार्यक्रम में खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लंदन के आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से जून महीने में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में शामिल होने और भाषण देने के लिए उन्हें निमंत्रण भेजा गया है। बताया कि लंदन स्कूल आफ इकोनॉमिक्स के छात्र भी मुख्यमंत्री को आमंत्रित हैं। कोलकाता में अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सबकुछ ठीक रहा तो मैं जून में लंदन का दौरा करूंगी। (राज्य)

फोटोग्राफी प्रतियोगिता में तेलंगाना पुलिस ने मारी बाजी
लखनऊ: लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस इयूटी मीट में तीसरे दिन फोटोग्राफी प्रतियोगिता में तेलंगाना पुलिस के कैदी विजय ने बाजी मारी। प्रतियोगिता में कैदी विजय से पूछा गया कि अधिकार क्राइम सीन में फोटोग्राफी क्यों आवश्यक है और इसमें क्या विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कैदी विजय ने जवाब दिया कि क्राइम सीन में फोटोग्राफी घटना के राजफाश में सबसे अधिक सहायक होती है। खास बात यह की घटनास्थल को फोटो दूर और नजदीक दोनों से करनी चाहिए, क्योंकि घटना के समय जब अधिकारी अथवा पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है तब उस समय हर चीज को बारीकी से नहीं देख पाते हैं। इसी तरह तेलंगाना पुलिस के पन्नी रमाना जिन्हें दूसरा मिला और तीसरा स्थान पाने वाले महाराष्ट्र पुलिस के वैतली गपत ने अपनी बारी पर परीक्षक को संतुष्ट किया। (जस)

हवलदार वरिंदर सिंह विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित
नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के हवलदार वरिंदर सिंह को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। हवलदार वरिंदर को यह सम्मान बहु-उद्देशीय आक्टोफाटर विकसित करने के लिए प्रदान किया गया है। वरिंदर द्वारा विकसित बहु-उद्देशीय आक्टोफाटर एक बहुमुखी ज्ञान है जो न केवल मिगारमी अभियान चलाने, बल्कि ड्रैनेज गिराने, एक-47 जैसे हथियारों के साथ हवाई लक्ष्य पर हमला करने और लाजिस्टिक्स आपरेशन में सहायक है। (एक्सप्रेस)

ईडी का तमिलनाडु के पूर्व मंत्री के विरुद्ध सुनवाई का आग्रह
चेन्नई: ईडी ने मद्रास हाई कोर्ट से द्रमुक नेता और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी संथिल बालाजी के विरुद्ध जाब-फार-कैश डेटाग्राफ का तमिल लेख लिखने पर विचार करने का आग्रह किया है। जस्टिस अनंद वैकटेश के समक्ष अपने शाब्दिक प्रश्नों में ईडी ने कहा है कि पूर्व मंत्री जानबूझकर मनी लाँड्रिंग मामले में सुनवाई शुरू होने से रोक रहे थे। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट से मुकदमा पूरा होने से पहले जमानत याचिका स्वीकार करने की जगह त्वरित सुनवाई का आग्रह किया। (आइएनएस)

केरल के स्कूल में देर रात पूजा की जांच के आदेश
कोडिगोड: कोडिगोड में सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त लोअर प्राथमिक विद्यालय में सोमवार रात एक नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। स्कूल प्राबंधन ने कक्षा के भीतर पूजा की और सप्ताहवारी पार्टी माफिक के कार्यक्रमों को रोक दिया। स्कूल प्राबंधन ने इसमें व्यवधान डाला। पुलिस ने कहा कि यह घटना कुटिलताओं के समीप नेदुमानुर लोअर प्राथमिक विद्यालय में हुई। मुद्दे पर विवाद उत्पन्न होने के बाद सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवानकुट्टी ने मंत्रालय को मामले की जांच का निर्देश दिया। (प्रेंड)

अभिनेत्री गौतमी अन्नाद्रमुक में शामिल हुईं
चेन्नई: लोकप्रिय फिल्म अभिनेत्री गौतमी तदिमालला ने बुधवार को अन्नाद्रमुक के महासचिव ईके पलानीस्वामी से मुलाकात की और तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हो गईं। 155 वर्षीया अभिनेत्री 120 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। (प्रेंड)

भाजपा ने संदेशखाली घटना की सीबीआइ जांच की मांग की

महिला आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जांच की मांग, लगातार सातवें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी

रजय ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल भाजपा प्रमुख कार के बोनट से गिरने से घायल



बंगाल के उत्तर 24 प्रदेस जिले में बुधवार को कार की बोनट पर खड़े होकर मीडिया से वार्ता के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार संतुलन बिगडने के साथ गिर पड़े।



संतुलन बिगडने की वजह से गिर पड़े प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उनका उपचार चल रहा है।

भाजपा की बंगाल इकाई के प्रमुख सुकांत मजुमदार उत्तर 24 प्रदेस जिले में बुधवार को कार के बोनट पर खड़े होकर पत्रकारों की संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान संतुलन बिगडने से गिर पड़े और चोटिल हो गए। उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मजुमदार ने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस ने उन्हें अशांत संदेशखाली जाने से रोकने के लिए उनके लाज की धमकी देकर उन्हें अशांत इन्कार किया है।

भाजपा ने ममता राज को बताया जंगल राज, मांगा इस्तीफा

जगरण ब्यूरो, नई दिल्ली: भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। ममता राज को जंगल राज बताते हुए इस्तीफा की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि बंगाल में दुकर्मियों की सरकार है, जो दुकर्मियों के द्वारा, दुकर्मियों के लिए चलाई जा रही है। बंगाल में टीएमसी के गुंडे द्वारा बंदूक की नोक पर महिलाओं से दुकर्म करने की मीडिया रिपोर्टें बहुत निराशाजनक और चिंतजनक हैं। कोलकाता हाईकोर्ट का इस मामले पर स्वतः सजान लेना ममता बनर्जी सरकार और उनके इरादों पर करारा थापड़ है।

ईसीएचएस प्रभारी अधिकारी को सीबीआइ ने किया गिरफ्तार

जगरण संवाददाता, बुलंदशहर: बुलंदशहर में पूर्व सैनिक अंशुदायी स्वस्थय योजना (ईसीएचएस) पाली क्लीनिक के प्रभारी अधिकारी अशोक कुमार शर्मा को बुधवार दोपहर सीबीआइ ने गिरफ्तार कर लिया है। इन पर कामकाज की सुचारु सुविधा के लिए एक लाख रुपये की मासिक रिश्तत मांगने के आरोप हैं। रिश्तत के 80 हजार रुपये लेते समय सीबीआइ टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बुलंदशहर में ईसीएचएस का दफ्तर व क्लीनिक है। यहां से पूर्व सैनिकों को संबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं के लिए रेफर किया जाता है। इस क्लीनिक के प्रभारी अशोक कुमार शर्मा नेबो के रिटायर्ड अधिकारी हैं। वह ग्रेटर नैपड़ा में रहते हैं। वह रोजाना घर से क्लीनिक आते हैं। सीबीआइ ने एक ट्रेप आपरेशन में क्लीनिक से ही इनको गिरफ्तार किया है। अशोक कुमार को गिरफ्तारी तब हुई जब वह एक व्यवसायी से 80 हजार रुपये की पहली किस्त प्राप्त कर रहे थे। आरोपित को गाजियाबाद की सीबीआइ अदालत पेश किया जाएगा।

मादी के जम्मू दौरे से पहले पाक ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन

जगरण संवाददाता, जम्मू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे से पहले पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तनाव बढ़ाने का प्रयास किया। जम्मू के सीमांत क्षेत्र आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी रजर्स ने बुधवार शाम को बिना किसी उकसावे के गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। बीएसएफ जवानों ने इसका करारा जवाब दिया। लगभग आधा घंटा हुई गोलीबारी में भारतीय क्षेत्र में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बीएसएफ ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। ग्रामीणों को भी सतर्क कर दिया है। पिछले वर्ष अक्टूबर में भी अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था जिसमें एक महिला के अलावा दो बीएसएफ जवान घायल हो गए थे। बता दें कि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री 20 फरवरी को जम्मू दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जम्मू में जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

पुलवामा हमले की वरसी पर आरएसपुरा में पाकिस्तानी रजर्स ने विना वजह की गोलीबारी

बीएसएफ के उच्च अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया, सीमा पर चौकसी बढ़ी

प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा है। ऐसे में पाकिस्तान खलल डालने का षड्यंत्र रच रहा है। बुधवार को पुलवामा हमले की बरसी भी थी। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान रजर्स ने अफजल सईद पोस्ट से गोलाबारी की। 6-10 बजे शुरू हुई गोलाबारी रुक-रुक कर 6-25 बजे तक जारी रही। बीएसएफ जवानों के मुंह तोड़ जवाब देने के बाद पाक की तरफ से गोलाबारी बंद हुई। इसके बाद बीएसएफ के उच्च अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस अधिकारी मौके पर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। सीमावर्ती लोग सतर्क कर दिए गए हैं। सुरक्षा अधिकारी के अनुसार सीमा पर फिलहाल हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। सुरक्षा एजेंसियां अभी स्थिति नजर बनाए हुए हैं।

छत्तीसगढ़ में खाली मकानों का ताला तोड़कर मुस्लिमों ने किया कब्जा

नईदुनिया, बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में हाउसिंग बोर्ड द्वारा पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए 50 मकानों का ताला तोड़कर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया है। दो घरों में अवैध निर्माण करते हुए वहां मजार बनाकर झाड़ू-फूंक शुरू कर दी है। कुछ ऐसे घर, जहां परिवार वाले रह रहे थे, आसपास के मुस्लिम परिवारों ने इन्हें धमकाकर घर खाली करवाने के बाद उन पर भी कब्जा कर लिया है। लोगों की शिकायत पर नगर निगम प्रबंधन ने कब्जा करने वाले 125 परिवारों को मकान खाली करने का नोटिस दिया है। हाउसिंग बोर्ड ने वर्ष 2013 में आवास विहिन परिवारों के लिए 400 मकान बनाए थे। इनमें से 335 मकान पात्र देखते ही हितग्राहियों को आवंटित कर दिए गए और बचे 65 मकानों पर ताला लगा दिया गया। कुछ परिवार इन आसपास के कुछ मुस्लिम परिवार इन बंद पड़े मकानों का ताला तोड़कर रहने लगे। धीरे-धीरे शहर के अन्य क्षेत्र के मुस्लिम भी मकान का ताला तोड़कर यहां रहने लगे। देखते ही देखते 50 से ज्यादा मुस्लिम परिवारों का इन मकानों पर कब्जा हो गया। आसपास रहने वाले मुस्लिम परिवारों ने पात्र हितग्राहियों को उधरकर मकान से बाहर

विलासपुर हाउसिंग बोर्ड कालोनी का मामला 125 लोगों को घर खाली करने का दिनांक नोटिस



हाउसिंग बोर्ड कालोनी देवरीखुर्द का वह मकान जिसमें कब्जाकारी ने मजारनुमा निर्माण कराया है।

शिकायत मिली है कि मकानों का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया गया है। ऐसे लोगों को मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है। मकान खाली नहीं करने की दशा में अग्रे की कार्रवाई की जाएगी। -सुरेश बरुआ, कार्यपालक अभियंता, नगर निगम

राम मंदिर को लेकर कर्नाटक विधानसभा में तीखी बहस

बंगलुरु, प्रेंड

बंगलुरु, प्रेंड: राम मंदिर और हनुमान ध्वजा के मुद्दे पर बुधवार को कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष दल भाजपा और सत्तारूढ़ कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई है। राज्य में कानून और व्यवस्था पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने दावा किया कि भाजपा असली कारसेवकों का अपमान कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के बेटे प्रियंक खरगे ने कहा कि भाजपा पहले शंकराचार्यों की आपत्तियों का जवाब दे। इस पर भाजपा नेता अशोक ने कहा कि कांग्रेस ने मंदिर के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि नहीं बनाने पर आपत्ति उठाई थी। वहीं भाजपा सदस्य सुनील कुमार ने कहा कि राम मंदिर हमारा मुद्दा है। इसके लिए हमारी प्रतिबद्धता थी। विपक्ष के नेता आर.अशोक ने सिद्धमैया प्रशासन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को जानबूझकर कमजोर किया गया। अशोक ने 1992 में रामजन्मभूमि आंदोलन में हुई हिंसा से जुड़े श्रैचक्रित पुजारी को कारसेवक कहते

भाजपा ने कहा-राम मंदिर हमारा मुदा, इसमें हमारी प्रतिबद्धता थी



कांग्रेस का आरोप-भाजपा असली कारसेवकों का अपमान कर रही

प्रियांक खरगे। फाइल

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफार्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच शफीकुर्रहमान पर सीएम योगी ने नहीं दिया बयान

विश्वास. News

क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है www.vishvasnews.com

नई दिल्ली, जेएनएन: आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व इंटरनेट मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद शफीकुर्रहमान बर्क के दो बयानों से संबंधित इन्फोग्राफिक्स को शेयर किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि शफीकुर्रहमान के एक बयान पर पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने भड़काऊ बयान दिया।



शफीकुर्रहमान के नाम से की-वर्ड सर्च में हमें एक यू-ट्यूब चैनल पर दो साल पुराना अपलोड किया हुआ वीडियो मिला, जिसमें उनका यह बयान सीधे-सीधे है। दावा प्रदेश सरकार की जनसंख्या नीति पर सवाल उठाते हुए सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने कहा था कि अगर इसकी वजह से जनसंख्या कम हो गई और दूसरे मुल्क से विवाद

वया हो रहा प्रसारित?

इंटरनेट मीडिया यूजर 'inshor0186' ने पोस्ट को शेयर किया है जिसमें योगी आदित्यनाथ और शफीकुर्रहमान के बयानों का जिक्र है। शफीकुर्रहमान के नाम से इस बयान का जिक्र है, 'अगर कच्चे पद नहीं होंगे तो बाईर पर कौन लड़ेगा?' वहीं योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ उनके नाम से बयान का जिक्र है, 'मियां यदि तुम लोग पद ही नही तो लखई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।' कई अन्य यूजर्स ने इसे समान दावे के साथ शेयर किया है।

के बयान के जवाबी पलटवार के दावे के साथ योगी आदित्यनाथ के नाम पर शेयर किया जा रहा बयान फेक और मंगद्वैत है।

झूठी खबर और अफवाहों का सच जानने के लिए विश्वास न्यूज के वाट्सएप चैनल को फॉलो करने के लिए कोड स्कैन करें।

बदलाव की अपील

अंग्रेजों के समय के नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट, पंजाब व हरियाणा को नोटिस

हाई कोर्ट में ए-3 साइज की जगह ए-4 कागज का इस्तेमाल करने की मांग पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस जीएस संघवालिया व जस्टिस लुपिता बनर्जी पर आधारित डिवीजन बेंच हाई कोर्ट (प्रशासनिक स्तर), पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि कागज प्रयोग करने को लेकर हाई कोर्ट में आज भी अंग्रेजों के नियमों के अनुसार कागज का इस्तेमाल हो रहा है। इससे न केवल कागज की जमकर बर्बादी हो रही है बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। अदालती कार्रवाई में कागज की खपत को कम करने और पर्यावरण को बचाने के लिए चंडीगढ़ निवासी विवेक तिवाड़ी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ए-3 साइज की जगह ए-4 कागज का इस्तेमाल करने की मांग की है। याचिका में हाई कोर्ट के साथ-साथ हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ की सभी अधीनस्थ अदालतों, टिब्यूनल में दायर की जाने वाली याचिकाओं, हलफनामे या अन्य दस्तावेजों के लिए एक तरफ छपाई के साथ लीगल पेज (ए 3) के उपयोग करने की वर्तमान प्रथा पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार फुलस्क्रेप पेपर पर, डबल स्पेसिंग के साथ, मार्जिन छोड़ कर शीट के केवल एक तरफ छपाई करने के आदेश को कागज की जबरदस्त बर्बादी होती है। याचिका के अनुसार यह नियम जो दशकों पहले तैयार किए गए थे, स्वतंत्रता-पूर्व औपनिवेशिक समय के हैं। उस समय कागज की मोटाई और स्याही की गुणवत्ता

हाई कोर्ट में ए-3 की जगह ए-4 कागज के इस्तेमाल की मांग

रजय ब्यूरो, चंडीगढ़

1 पेड़ को काटकर उससे कागज की लगभग 8333 शीट का उत्पादन किया जाता है

10 लीटर पानी की आवश्यकता होती है कागज का एक टुकड़ा हिस्सा तैयार करने के लिए

1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 के बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष 1,46,045 मामले दायर

याचिका में बताया गया पानी और पेड़ों की वचत का हिसाब-किताब भारतीय न्यायपालिका की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 के बीच पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष कुल एक लाख 46 हजार 45 मामलों दायर किए गए। एक सामान्य अनुमान के लिए मान लेते हैं कि इन्हीं से प्रत्येक मामले के कारण कागज के एक तरफ छपी स्याही दूसरी तरफ रिस जाती थी, जिससे पढ़ने मुश्किल हो जाता था। अब पेपर प्रिंटिंग तकनीक और स्याही से संबंधित तकनीकों की प्रगति के चलते यह समस्या नहीं रही है। जानकारों के अनुसार मामला पर्यावरण के हित को ध्यान में रखकर उठाया गया है। इससे लिए नजीर बन सकती है।

जब मोदी महाराष्ट्र का दौरा करेंगे तो जरांगे अपने स्थान से हिल भी नहीं पाएंगे: राणे

मुंबई प्रेंड: केंद्रीय मंत्री नाचरण राणे ने महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को बाधित करने की धमकी देने की गंभीरता से लिया और मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनीज जरांगे पर निशाना साधा। राणे ने एक्स पर लिखा कि भूख हड़ताल पर बैठे जरांगे ने सारी हदें पार कर दी हैं। कहा कि जरांगे ने एक बेटुकी और संबेदनहीन टिप्पणी की है कि वह महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को मुश्किल कर देंगे। उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। मैं आपकी चुनौती देता हूँ कि जब प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र का दौरा करेंगे तो आप अपने स्थान से हिल भी नहीं पाएंगे। मैं उन्हें मराठाओं का नेता नहीं मानता। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ मानसिक झटका लगा है। वह ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। कहा कि उन्हें अपनी सीमाएं जाननी चाहिए और हद में रहना

जब मोदी महाराष्ट्र का दौरा करेंगे तो जरांगे अपने स्थान से हिल भी नहीं पाएंगे: राणे

मुंबई प्रेंड: केंद्रीय मंत्री नाचरण राणे ने महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को बाधित करने की धमकी देने की गंभीरता से लिया और मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनीज जरांगे पर निशाना साधा। राणे ने एक्स पर लिखा कि भूख हड़ताल पर बैठे जरांगे ने सारी हदें पार कर दी हैं। कहा कि जरांगे ने एक बेटुकी और संबेदनहीन टिप्पणी की है कि वह महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को मुश्किल कर देंगे। उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। मैं आपकी चुनौती देता हूँ कि जब प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र का दौरा करेंगे तो आप अपने स्थान से हिल भी नहीं पाएंगे। मैं उन्हें मराठाओं का नेता नहीं मानता। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ मानसिक झटका लगा है। वह ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। कहा कि उन्हें अपनी सीमाएं जाननी चाहिए और हद में रहना



केंद्रीय मंत्री ने पीएम की रैलियों को बाधित करने की धमकी देने पर जरांगे पर साधा निशाना

चाहिए। नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के लिए मराठा समुदाय के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जरांगे पिछले पांच दिनों से अंतरवाली जिले में अपने पैतृक गांव जालनवाली सरिता के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। जरांगे ने चेतावनी दी थी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी की कोई भी जनसभा नहीं होने दी जाएगी। जरांगे ने कुनबी मराठी के रक्त संबंधियों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने पर कानून में बदलाव के लिए राज्य विधानमंडल का एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की है।

देशों के लिए सिरदर्द बना किसानों का ट्रैक्टर मार्च

इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, वेंजुएला, रोमानिया और ग्रीस सहित कई देशों में किसान ट्रैक्टर के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत में भी सुरक्षा एजेंसियां किसानों के ट्रैक्टर मार्च से निपटने के लिए कारगर उपाय बताशा रही हैं। आइये जानते हैं वैश्विक स्तर पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च का ट्रेंड किस तरह से जोर पकड़ रहा है?



इटली

किसानों ने हाल में ट्रैक्स लुट फिर से लागू किए जाने की मांग को लेकर ट्रैक्टर के एक काफिले के साथ रोम में प्रदर्शन किया। पहले किसान ट्रैक्टर के साथ बड़ी रैली करना चाहते थे लेकिन आम लोगों को होने वाली असुविधा और उनका समर्थन खोने की आशंका के चलते उन्होंने ट्रैक्टर के छोटे काफिले के साथ प्रदर्शन किया।



स्पेन

स्पेन के विटोरिया शहर में किसानों ने सड़क पर ट्रैक्टर मार्च निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया। इससे ट्रैकिंग बाधित हुआ। किसान बढ़ती कीमती, लालपीताशाही और बाहर से सरसते आयात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्पेन में किसानों ने ट्रैक्टर के काफिले के साथ राजमार्ग और बंदरगाह भी जाम किए।



जर्मनी

किसानों ने जनवरी में पूरे जर्मनी में ट्रैक्टर मार्च निकाल कर सड़कों को जाम कर दिया। किसान सरकार की सख्ती में कटौती की योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले दिसंबर में हजारों किसानों ने बर्लिन में विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कें जाम कर दी थीं और सड़कों पर खाद गिरा दी थी।



वेंजुएला

31 जनवरी को हजारों किसान ट्रैक्टर के साथ बुसेल्स में यूरोपीय संसद के सामने विरोध प्रदर्शन किया। किसान बढ़ती कीमती और ट्रैक्स की ऊंची दरों से नाराज हैं। यहां किसानों ने पुलिस पर अंडे और पटाखे भी फेंके। किसानों का प्रदर्शन जारी है और उनकी धरती की बंदरगाह का परिचालन भी बाधित हो रहा है।



फ्रांस

30 जनवरी को करीब 10,000 किसानों ने ट्रैक्टर के काफिले के साथ विरोध प्रदर्शन किया और राजमार्ग जाम कर दिया। फ्रांस में सरकार ने किसानों को बड़े शहरों से दूर रहने की चेतावनी दी है। फ्रांस में भी किसान ज्यादा धुतान, नौकरशाही पर अंकुश और विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की मांग कर रहे हैं।

न्यूज गेलरी

किसानों की मांगें गंभीरता से ले केंद्र सरकार : मायावती

लखनऊ : बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार को किसानों की मांगों को गंभीरता से लेने की सलाह दी है। इंडरनेट मीडिया एकाउंट एक्स पर बुधवार को किए गए पोस्ट में मायावती ने सरकार को किसान आंदोलन पर सख्ती करने के बजाए उनसे वार्ता कर आंदोलन समाप्त करने का प्रयास करने की नसीहत दी है। मायावती ने लिखा, महहनतकश किसानों की जो मांगें हैं, सरकार उन्हें गंभीरता से ले। (राज्य)

उतारे गए किसानों को पुलिस ने अयोध्या की ट्रेन में बैठाया

उज्जैन : किसानों के समर्थन में दिल्ली जा रहे कर्नाटक के जिन 70 किसानों को मध्य प्रदेश पुलिस ने सोमवार को भोपाल स्टेशन पर उतार लिया था, उन्हें बुधवार को अयोध्या जा रही ट्रेन में बिना टिकट चढ़ाकर भेज दिया। किसानों के साथ एक रिपार्टी को भी भेजा गया है। इससे पहले किसानों को को पैसेजर ट्रेन में बैठाकर उज्जैन लाया गया था। वहां किसानों को महाकाल मंदिर में दर्शन कराने के बाद एक गार्डन में नजरबंद कर दिया गया था। अयोध्या की ट्रेन में बैठाते समय किसानों ने कहा कि उन्हें जबरिया भेजा जा रहा है। जाना दिल्ली है और भेज अयोध्या रहे हैं। (नईदिल्ली)

स्वामीनाथन की वेंटी ने कहा, किसानों को साथ लें

पश्चिमी दिल्ली : हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने की खुशी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें एमएस स्वामीनाथन की वेंटीयों ने आनलाइन हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। स्वामीनाथन की वेंटी मधुरा स्वामीनाथन ने कहा कि हमें एमएस स्वामीनाथन का सम्मान करना है, तो भविष्य के लिए हम जो भी रणनीति बना रहे हैं उसमें हमें किसानों को अपने साथ लेना होगा। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञानियों को किसानों से परामर्श करना चाहिए। उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। (जस)

पीएम मोदी को धमकी वाले वीडियो हो रहे प्रसारित

चंडीगढ़ : हरियाणा की सख्ती से दिल्ली कूच में विफल होने के कारण कुछ किसान अपना आगो खो रहे हैं। वे न केवल भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि इंडरनेट मीडिया पर प्रचारमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देने वाले वीडियो भी प्रसारित हो रहे हैं। इन धमकीयों की जांच कर रही साइबर सेल के मुताबिक, कुछ ऐसे वीडियो प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें प्रचारमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी जा रही है कि पिछली बार वह फिरोजपुर में बच निकले थे, लेकिन इस बार आप तो जिंदा नहीं जाएंगे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, जांच के बाद एक आइआर दर्ज की जाएगी। ध्यान रहे कि प्रतिबंधित संगठन सिख फार जस्टिस के आतंकी गुरपतवत सिंह पन्नू की ओर से लातार बंदरनेट मीडिया पर भारतीय को खराब करने के लिए पोस्ट डाली जा रही है। (राज्य)

दस के दम के सहारे किसानों के प्रदर्शन के सामने डटी भाजपा

'अन्नदाता का सम्मान' हैशटैग के साथ सक्रिय हुई भाजपा

प्रदर्शन विरुद्ध इंटरनेट मीडिया पर संभाला मोर्चा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

तमाम प्रयासों और निर्णयों से जिन खेत-खलिहान में भाजपा अपनी चुनबी जमीन पकची मान रही है, विपक्षी दल उसे ही कच्ची जमीन समझकर दंगल सजाने के लिए प्रदर्शनकारियों के पीछे हो लिए हैं। विपक्षी दलों की ओर से किसान संगठनों के उग्र 'दिल्ली कूच' को भरपूर हवा दी जा रही है, वहीं भाजपा को मोदी सरकार के दस वर्षों के कार्यकाल में किसानों के हित में लिए गए निर्णयों पर धरोसा है। भाजपा ने किसानों के घर-घर दस्तक के अलावा इंटरनेट मीडिया पर भी मोर्चा संभाल लिया है।

मोदी सरकार ने गांव, गरीब व किसान को प्राथमिकता में रखा। 11 करोड़ से अधिक किसानों को सम्मान निधि सहित कई निर्णयों से भाजपा ने ग्रामीणों-किसानों में पैठ बढ़ाई, जिसका परिणाम 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दिया। किसानों के बोटबैंक में सेंध लगाने की जुगत फिर से शुरू हुई है। इंटरनेट मीडिया पर भी विपक्षी दल सक्रिय हैं और भाजपा को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार किसानों से बाती जरूर कर रही है, पर प्रदर्शनों को लेकर संशकित नहीं है। किसान मोर्चा को ग्राम परिष्कार यात्रा के जरिये मोदी सरकार के किए कार्यों का पुनः गांव-गांव, घर-घर जाकर प्रचार किया जा रहा है। साथ ही भाजपा ने 'अन्नदाता का सम्मान' हैशटैग से सरकार के निर्णय इंटरनेट मीडिया पर गिनते हुए भी मोर्चा संभाल लिया है।

भाजपा ने याद दिलाए मोदी सरकार के कुछ निर्णय

- पीएम किसान मानवण योजना में तीन हजार रुपये प्रतिमाह पेशन 123.38 लाख किसानों का पंजीकरण।
- पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना को कैबिनेट की मंजूरी। 2023-24 से 2026-27 तक छह हजार करोड़ से अधिक का निवेश।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 2400 करोड़ रुपये का आवंटन। दुग्ध उत्पादन में हुई 61 प्रतिशत की वृद्धि।
- सोलर पंप पर अनुदान मिलने से बड़ी पंपों की संख्या। 1992 से 2014 तक 0.116 लाख तो 2014 से 2023 के

- बीच लगे 5.3 लाख सोलर पंप।
- प्रसंस्कारित खाद्य पदार्थों के निर्यात में दोगुणी बढ़ोतरी। 12014-15 की तुलना में 2022-23 में निर्यात दर 13.7 प्रतिशत से बढ़कर हुई 25.6 प्रतिशत।
- खाद्य उत्पादन क्षमता 15 गुना बढ़ी। 2014 में 12 लाख मीट्रिक टन, 2023 में 200 लाख मीट्रिक टन उत्पादन।
- चना, मसूर, जौ आदि के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी।
- फसल खरीद 40% बढ़ी। 2014-15 में यह 759 लाख मीट्रिक टन थी, जबकि 2023 में 1063 लाख मीट्रिक टन।



पंजाब-हरियाणा सीमा पर कूच पर को प्रदर्शनकारी किसान एवं मुस्तेद सुरक्षाकर्मी। प्रशासन ने पिछले अनुभव से सबक लेते हुए इस बार पण्डित इतजाम कर रहे हैं। एपी

एमएसपी को लेकर राहुल की गारंटी पर किसानों को नहीं भरोसा

इंद्रवीर सिंह, शंभू (पटियाला)

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की गारंटी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए आश्वासन पर किसान नेताओं को ही भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी के लिए कानून बनाने का राहुल का बयान राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान आई थी, पर लागू नहीं की गई। दिलचस्प यह कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहीं भी एमएसपी का कानून बनाने की बात नहीं थी, सिर्फ किसानों को उनकी फसल की लागत पर 50 प्रतिशत लाभ देने की बात थी।

गुरुदासपुर से आए किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता बलकार सिंह ने कहा, हमें तो एमएसपी के मामले पर हद सरकार ने उठा है। पहले कांग्रेस से कि हमसे गेहूं व धान उगवा लिया जाता एमएसपी मांगते रहे, उनको सरकार गई तो मोदी ने रेखाड़ी की रैली में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी, पर रिपोर्ट लागू नहीं हुई। फिरोजपुर के जोगिंदर सिंह बोलें, अब किसानों की बातां

स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को कांग्रेस ने किया था खारिज

किसान नेता वोलें, राहुल गांधी का वयान सिर्फ राजनीतिक

एक किसान ने कहा, कांग्रेस नेता को इतनी ही फिक्र है तो साथ आए

पर कौन भरोसा करेगा। अगर उन्हें हमारी इतनी फिक्र है तो अपनी यात्रा छोड़कर हमारे साथ आए। बात स्वामीनाथन रिपोर्ट की नहीं है, फसलों के उचित मूल्य देने व खरीद के उचित बंदोबस्त की है। भारतीय किसान यूनियन आजाद के जर्नेल सिंह ने कहा, ये गारंटीयां चुनाव के दौरान ही क्यों यद आती हैं। क्या इन्हें लागू करने के लिए राहुल के पास दस साल का समय कम था। स्वामीनाथन आयोग का गठन कांग्रेस ने किया, रिपोर्ट उसी के कार्यकाल में आई। फिर भी आज हमें आंदोलनों का सहारा लेना पड़ रहा है। कहा, जब देश को जरूरत होती है तो हमसे गेहूं व धान उगवा लिया जाता है। जरूरत नहीं होती तो खरीदने में भी तो आनकानी करते हैं। धान के कारण हमारी जमीन का पानी खत्म हो गया है। मिट्टी बर्बाद हो गई है, लेकिन राजनीतिक लोगों को चुनाव आते ही बयान याद आते हैं।

जगरण ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रदर्शनकारी किसानों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है कि जब केंद्र में उनकी सरकार बनेगी तब एमएसपी की मांग पूरी की जाएगी, किंतु सच यह भी है कि वर्ष 2010 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को खारिज कर दिया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी कांग्रेस के कार्यकाल में ही वर्ष 2006-07 में सौंपी थी।

वर्ष 2010 में राज्यसभा में भाजपा सांसद प्रकाश जावड़ेकर के संबंध्यित एक प्रश्न पर केंद्र सरकार की तरफ से जवाब देते हुए कृषि मंत्रालय में तत्कालीन खंड एवं उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री केवी थामस ने कहा था कि इससे एमएसपी एवं उत्पादन लागत के बीच का संतुलन बिगड़ सकता है। जावड़ेकर ने पूछा था कि क्या सरकार ने किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को खारिज कर दिया है? इस पर जवाब देते हुए थामस ने कहा था कि आयोग की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है।

किसानों को पंजाब ने क्यों नहीं रोका : विज

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

किसानों के दिल्ली कूच को लेकर पंजाब व हरियाणा आमने आमने सामने आ गए हैं। हरियाणा में घुसने की कोशिश कर रहे किसानों पर शंभू बाईर पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागने पर पंजाब ने आपत्ति जताई तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, जब अमृतसर से किसान चले तो पंजाब सरकार ने इन्हें रास्ते में एक भी जगह रोकने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब यह है कि ये दिल्ली को दहलाना चाहते हैं, क्या देवबारा चाहते हैं कि दिल्ली के लाल किले में जाकर डांस कर अपमानित किया जाए।

अनिल विज ने अंबाला में कहा, बड़ी हैरानी की बात है कि पंजाब सरकार ने नोटिस जारी किया कि हमारी सीमा में ड्रोन मत भेजो, क्या यह हिंदुस्तान-पाकिस्तान हो गया। अगर, हमारी पुलिस को मारकर कोई पंजाब में भाग जाएगा तो क्या हम उसे पकड़ नहीं सकते। पूछा कि किसानों को दिल्ली किस लिए जाना है, जिनसे इनको बात करनी है? वे सारे मंत्री व अधिकारी चंडीगढ़ आ गए तो बात नहीं की। इनका मकसद कुछ और है। अंबाला के पास शंभू बाईर पर किसान जिस जगह जमा हैं, वह हिस्सा पंजाब

गृह मंत्री वोलें, ये लाल किले में डांस कर अपमानित करना चाहते हैं



अनिल विज। फाइल

के पटियाला जिले में आता है। पटियाला के उपायुक्त शोकर अहमद ने अंबाला के उपायुक्त को पत्र लिखकर पंजाब की सीमा में ड्रोन उड़ाने और आंसू गैस के गोले गिराने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, हरियाणा प्रशासन अपनी सीमा में कार्रवाई करे। पंजाब के पनआरआइ मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा, हरियाणा पुलिस की कार्रवाई आपत्तिजनक है। पंजाब का माहौल बिगाड़ने को कार्रवाई को किसी भी सूत्र में बंदरिस्त नहीं किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस के बरिष्ठ नेता नवजोत सिद्धू ने इंटरनेट मीडिया पर उक्तसंने वाली पोस्ट की है। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने क्षेत्र की रक्षा करें।

ड्रोन को गिराने के लिए किसान उड़ा रहे पतंग

शंभू बाईर पर जमे किसान ड्रोन को गिराने के लिए पतंग उड़ा रहे हैं। आंसू गैस के गोलों को निष्प्राभावी करने के लिए टाट की गीली बोरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसान खेतों में कीटनाशक दवाई छिड़कने वाली मशीनों से प्रेशर के साथ पानी बौझ कर रहे हैं ताकि आंसू गैस के प्रभाव को कम किया जा सके।

खनौरी बाईर पर हरियाणा पुलिस के जवान को पकड़ा

पंजाब के संगरूर जिले के खनौरी बाईर के अंदर किसानों ने हरियाणा पुलिस के एक जवान सतविंदर को पकड़ लिया। यह जवान खनौरी भावंतमान से भी बैठक के किसानों के बीच घूम रहा था। किसानों को शक था कि यह व्यक्ति उनकी जासूसी करने आया है। किसानों ने उसे पातड़ पुलिस के हवाले कर दिया है।

उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी की तरह हमें संघीय ढांच को रक्षा करनी चाहिए। जब सीबीआइ अफसर बंगाल पहुंचे थे तो उन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया था।

विरोध का असर पंजाब के कारोबारियों का हो रहा रोजाना 1000 करोड़ का नुकसान

पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर को रोज हो रहा 3000 करोड़ का नुकसान, 1500 से अधिक ट्रकों की आवाजाही पर किसान आंदोलन से लगा ब्रेक

गुरभीत ल्यरा, अमृतसर

किसानों के विरोध प्रदर्शन की कारोबार पर भी मार पड़ रही है। सिर्फ पंजाब, जम्मू-कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में प्रतिदिन तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार प्रभावित हो रहा है। अकेले पंजाब को 800 से 1000 करोड़ रुपये रोजाना का नुकसान उठाना पड़ रहा है। चिंतित कारोबारियों ने सरकार से अपील की है कि जल्द समाधान निकाला जाए ताकि नुकसान रोका जा सके।

पंजाब व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्यारे लाल सेठ एवं महासचिव समीर जैन ने कहा, अगर इसी तरह अर्थव्यवस्था पर चोट लगती रही तो देश की आर्थिक स्थिति बंद से बदतर हो जाएगी। लघु उद्योग भारतीय के अध्यक्ष अमित कपूर ने कहा, 90 प्रतिशत से अधिक माल सड़क मार्ग से ही पंजाब में पहुंचता है। ट्रकों की आजाही प्रभावित होने से कारोबारियों को माल की किल्लत महसूस होने लगी है।



प्यारे लाल सेठ एवं समीर जैन

हिमाचल में उत्पादन प्रभावित

जाय, शिमला : हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बदी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) में उद्योगियों ने उत्पादन कम कर दिया है। औद्योगिक क्षेत्र से दिल्ली की तरफ जाने वाले ट्रकों को कई क्ल बंदलने पड़ रहे हैं। इससे ट्रक अपारेंटों को नुकसान हो रहा है।

जरूरी दवाइयों अन्य राज्यों से नहीं पहुंच पा रही हैं।

इंडस्ट्री के पास दस दिन का ही है कंटा मीटर : लुधियाना का उद्योग जगत भी चिंतित है। फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन के पूर्व अध्यक्ष एवं लुधियाना हैट्टल एक्सपोर्टेशन के अध्यक्ष एससी रलहन ने कहा कि कच्चे माल की आमद न होने से इंडस्ट्री की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। इस समय मैटैरियल को लाना और ले जाना सबसे बड़ी चुनौती है। इंडस्ट्री के पास अगले

मुश्किल में दिल्ली का पर्यटन उद्योग, होटलों की बुकिंग में 40 प्रतिशत तक गिरावट

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली : किसानों के दिल्ली कूच से दिल्ली का पर्यटन उद्योग मुश्किल में आ गया है। न सिर्फ होटल के कमरों की बुकिंग में गिरावट आई है, बल्कि पहले ही चुकी बुकिंग को भी निरस्त किया जाने लगा है। इसमें देशी-विदेशी दोनों पर्यटक हैं। दिल्ली में पर्यटन से जुड़े लोगों के अनुसार किसानों के दिल्ली कूच करने और उन्हें रोकने के लिए बाईर पर भारी सुरक्षा व्यवस्था से बाकी राज्यों से दिल्ली का सड़क मार्ग प्रभावित हो गया है। जाम और असुरक्षित हालातों से बचने के लिए दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है। होटल महासंघ के अध्यक्ष अजय अग्रवाल के अनुसार अगर पहाड़ों को ही ले, तो यहाँ 700 से अधिक होटलों में 14 हजार से अधिक कमरे हैं, जिसमें एक दिन में तकरीबन 25 हजार लोग रुक सकते हैं। अमूमन यहां के होटलों के कमरे 80 से 90 प्रतिशत तक भरे रहते हैं, लेकिन दो-तीन दिन से बुकिंग पूरी तरह से बंद है। इस स्थिति में कमरों में पर्यटकों की मौजूदगी बमुश्किल 30 प्रतिशत रह गई है।

प्रथम गृह से आगे

किसान नेता सरकार से तीसरी बार बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। उनकी केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ गुरुवार शाम पांच बजे चंडीगढ़ के महात्मा गांधी स्टेट इस्टीमेट आफ पब्लिक एडमिस्ट्रेशन में बैठक होगी। राजपुरा की एमएसपीएस जसलीन कौर गुल्लर और इटलीजोस के एडिजीपी धुलकरण सिंह ने बंद कमरे में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के जगजीत सिंह डल्लेवाल, किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पेंघेर से बातचीत कराई।

बाद में किसान नेताओं ने प्रेस कांफ्रेंस में बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि

अब किसान शंभू बाईर पर बैठक से पहले आगे नहीं बढ़ेंगे

अब किसान शंभू बाईर पर बैठक से पहले आगे नहीं बढ़ेंगे। उधर, डल्लेवाल ने मुख्यमंत्री भावंतमान से भी बैठक में शामिल होने की अपील की है। बैठक का नोटिस किसानों को भेज दिया गया है। किसान दोपहर से ही मांग कर रहे थे कि बैठक का नोटिस उन्हें लिखित तौर पर दिया जाए।

केंद्र ने मंगलवार को हमें बातचीत के लिए संदेश भेजा था। हमने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को बात भी अखबारों में पढ़ी कि केंद्र सरकार किसानों के पक्ष में है। इसके बाद हमने संगठन के लोगों से बात की कि बैठक की जाय कि नहीं। सभी ने कहा कि बैठक करने चाहिए। इसके बाद हमने बैठक में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली।



अदाणी ग्रीन एनर्जी, सौर और पवन के लिए दुनिया के सबसे व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा परिवेश में से एक निर्माण कर रही है।
— गौतम अदाणी, चेयरमैन, अदाणी समूह

संसेक्स	71,822.83 267.64	निफ्टी	21,840.05 96.80	सोना प्रति 10 ग्राम	₹ 62,350 ₹ 750	चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 74,000 ₹ 1400	डॉलर	₹ 83.02 ₹ 0.06	कूड (बैट) प्रति बैरल	\$ 82.64
---------	---------------------	--------	--------------------	---------------------	-------------------	-----------------------	--------------------	------	-------------------	----------------------	----------

एक नजर में

अर्थव्यवस्था की समीक्षा करेंगी निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की 21 फरवरी को होने वाली बैठक में वैश्विक चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगी। उच्चस्तरीय निकाय की राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली 28वीं बैठक में आरबीआइ गवर्नर शक्तिशाली दास समेत वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामक शामिल होंगे। (प्रैट)

जनवरी में यात्री वाहनों की विक्री ने बनाया रिकार्ड

नई दिल्ली: यूटिलिटी वाहनों की मजबूत मांग के बीच घरेलू यात्री वाहनों की थोक विक्री जनवरी में सालाना आधार पर 14 प्रतिशत बढ़कर 3,93,074 इकाई हो गई। यह जनवरी में अभी तक दर्ज विक्री का सर्वाधिक आंकड़ा है। दोपहिया वाहनों की थोक विक्री जनवरी में सालाना आधार पर 26 प्रतिशत की बढ़त के साथ 14,95,183 इकाई रही। (प्रैट)

500 अस्पताल 'ईट राइट कैम्प' के रूप में प्रमाणित

नई दिल्ली: खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसआइ ने 500 से अधिक अस्पतालों को 'ईट राइट कैम्प' के रूप में प्रमाणित किया है। इसमें 100 सरकारी अस्पताल हैं। यह पहल नियामक के 'ईट राइट इंडिया' अभियान के तहत अस्पतालों सहित विभिन्न संस्थानों और कार्यस्थलों के भीतर सुरक्षित, स्वस्थ एवं पर्यावरण अनुकूल खाद्य परिवेश बनाने पर केंद्रित है। (प्रैट)

सात प्रमुख शहरों में लकड़ी घरो की विक्री 75% बढ़ी

नई दिल्ली: पिछले साल देश के सात प्रमुख शहरों में चार करोड़ रुपये से अधिक कीमत के घरों की विक्री में 75 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखी गई। रियल एस्टेट सत्याकार कंपनी सीबीआरआई के मुताबिक, सात प्रमुख शहरों में से दिल्ली-एमसीआर में लकड़ी घरो की विक्री में लगभग तीन गुना का उछाल आया। साल 2023 में 3,22,000 इकाई हो गई जो सालाना आधार पर नौ प्रतिशत अधिक है। (प्रैट)

यूरोपीय यूनियन को निर्यात करना होगा मुश्किल

वस्तु के उत्पादन में जंगल की कटाई से संबंधित जानकारी देने के नियम को लागू कर सकता है ईयू

राजीव कुंजर • नई दिल्ली

कार्बन बाईंडर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएम) के बाद यूरोपीय यूनियन (ईयू) अब वस्तु की बिक्री के लिए उस वस्तु के उत्पादन या निर्माण में जंगल की कटाई संबंधित जानकारी देने के नियम को लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। वस्तु के पैकेट पर व्युत्पन्न कोड के जरिये इसकी जानकारी देनी पड़ेगी कि उस वस्तु का निर्माण या उत्पादन में किस हद तक जंगल की कटाई हुई है। इसके तीन स्तर होंगे। उच्च, मध्यम व निम्न। उच्चस्तर का मतलब होगा कि वस्तु के निर्माण में जंगल की कटाई काफी अधिक हुई है।

वस्तु के पैकेट पर व्युत्पन्न कोड से देनी होगी जानकारी, वदेगी लागत



यूरोपीय यूनियन निम्न स्तर वाले उत्पादों की ही खरीदारी करेगा। इस प्रकार के नियम के लागू होने पर भारत को यूरोप में अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए अधिक व्युत्पन्न कोड देना पड़ेगा। इससे वस्तु निर्माण की लागत बढ़ जाएगी। यूरोपीय यूनियन (ईयू)

वर्ष 2026 से अपने यहां सीबीएम लागू करेगा यूरोपीय यूनियन

ईयू ने वर्ष 2026 से अपने यहां सीबीएम लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत वस्तु के निर्माण के दौरान कार्बन उत्सर्जन करने पर कार्बन टैक्स देना होगा। इससे स्टील, एल्यूमिनियम जैसी वस्तुओं का निर्यात महंगा हो जाएगा, क्योंकि इनके उत्पादन में काफी अधिक कार्बन का उत्सर्जन होता है। इससे भारतीय उत्पाद यूरोप में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। हालांकि भारत ने इस प्रकार की बाधाओं से बचने के लिए घरेलू स्तर पर ग्रीन स्टील व अन्य वस्तुओं के उत्पादन में ग्रीन ईंधन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है।

भारत कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए मांग सकता है फंड

सूत्रों के मुताबिक भारत यह नहीं कह रहा है कि हम कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लागू जा रहे नियमों का पालन नहीं करेंगे, लेकिन भारत ईयू व अन्य विकसित देशों को इस प्रकार के नियमों के पालन के लिए उनसे टेक्नोलॉजी व फंड मुहैया कराने की मांग करेगा। डब्ल्यूटीओ की एमसी13 की बैठक में भारत इस प्रकार के रुख को अपना सकता है।

तीन महीने के निचले स्तर पर रही थोक महंगाई

नई दिल्ली, प्रैट: थोक मुद्रास्फोति जनवरी में तीन महीने के निचले स्तर 0.27 प्रतिशत पर आ गई। खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी इसकी प्रमुख वजह रही। दिसंबर 2023 में यह 0.73 प्रतिशत थी जबकि जनवरी, 2023 में यह 4.8 प्रतिशत थी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फोति अप्रैल से अक्टूबर तक लगातार शून्य से नीचे बनी हुई थी। नवंबर में यह 0.39 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

आरबीआइ ने कहा, बढ़ते जोखिमों के प्रति सतर्क रहें बैंक प्रबंधन

मुंबई, प्रैट: आरबीआइ गवर्नर शक्तिशाली दास ने बुधवार को बैंकों से क्षेत्र में बढ़ते जोखिमों के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आत्मसंतुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं है। गवर्नर ने सर्वांगिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के चुनिंदा बैंकों के प्रबंध निदेशकों (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के साथ बैठक की। यह आरबीआइ की बैंकों, एनबीएफसी और दायरे में आने वाली अन्य इकाइयों के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बातचीत करने की मुहिम का हिस्सा है।

आरबीआइ ने एक बयान में कहा कि गवर्नर ने बैंकों के बेहतर वित्तीय प्रदर्शन के लिए उनकी सहायता की। बयान के अनुसार, 'बैंकों की बेहतर बैलेंस शीट के साथ घरेलू वित्तीय प्रणाली की मजबूती पर गौर करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की डिग्लाइंड की कोई गुंजाइश नहीं है और बैंकों को बढ़ते जोखिमों को लेकर अपनी निगरानी बनाए रखनी चाहिए।' दास ने बिजनेस माडल की व्यवहार्यता, व्यक्तिगत ऋणों में अत्यधिक वृद्धि, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र में बैंक के कर्ज और नकदी जोखिम प्रबंधन से जुड़े मुद्दों का भी जिक्र किया। बैठक में बैंकों को फिनटेक संबंधित पहल में भाग लेने को कहा गया।



आरबीआइ गवर्नर शक्तिशाली दास

वित्त आयोग की पहली बैठक में अधिकारों और उद्देश्यों पर हुई चर्चा

जायू, नई दिल्ली: डा. अरविंद पानागढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक में आयोग के संचालन को लेकर कई अहम फैसले किए गए। बैठक में आयोग के अधिकारों व उद्देश्यों को लेकर चर्चा हुई और आने वाले दिनों में राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, विभिन्न मंत्रालयों और विशेषज्ञों से किस तरह से विमर्श को आगे बढ़ाया जाएगा।

आयोग की तरफ से शोध संस्थानों, थिंक टैंक से भी विमर्श की जरूरत को चिन्हित किया गया है। आयोग की तरफ से स्वीकार किया गया है कि उसे बहुत बड़े स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ बातचीत करनी होगी। आयोग की तरफ से पहली सिफारिशों 31 अक्टूबर, 2025 को सकार करने की सौंप जाएगी। 01 अप्रैल, 2026 से पांच वर्षों के लिए इसकी रिपोर्टों के आधार पर केंद्र सरकार और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा किया जाएगा।

आरआईएल ने बाजार पूंजीकरण में पेप्सिको व पेट्रोचाइना को पीछे छोड़ा

मुंबई, प्रैट: मुकेश अंबानी की अगुआई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) बुधवार को 20 लाख करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली देश की राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, विभिन्न मंत्रालयों और विशेषज्ञों से किस तरह से विमर्श को आगे बढ़ाया जाएगा।



माइक्रोसाफ्ट कार्प	3.08 ट्रिलियन डॉलर
एपल इंक	2.89 ट्रिलियन डॉलर
सऊदी अरामको	2.04 ट्रिलियन डॉलर
अल्फाबेट इंक	1.84 ट्रिलियन डॉलर

20.05 लाख करोड़ रुपये हो गया। इस उपलब्धि के साथ कंपनी बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया की शीर्ष 50 कंपनियों में पेप्सिको, शेल पीपलसी और सिस्को जैसी दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ 49वें स्थान पर पहुंच गई है। खास बात यह है कि अगर 20 जुलाई, 2023 को रिलायंस से अलग हुई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एम-कैप को इसमें शामिल कर लिया जाए तो रिलायंस का संयुक्त बाजार मूल्यांकन 21.73 लाख करोड़ रुपये होगा। इससे कंपनी 43वें स्थान पर हो जाएगी। इससे यह एक्सचेंज और नेटफ्लिक्स से भी आगे हो जाएगी।

बेहमई कांड में 43 साल बाद एक को उम्र कैद, एक बरी

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात

कानपुर देहात के बेहमई गांव में 43 वर्ष पहले हुए नरसंहार पर बुधवार को फैसला आ गया। घटना में दस्यु रहीं फूलन देवी समेत 36 आरोपित बनाए गए थे। फूलन देवी समेत 33 आरोपित अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक अब तक फरार है, वहीं दो लोग जमानत पर चल रहे थे। इनमें से एक को देशी ठहराते हुए एंटी डकैती कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। घटना 1981 में 14 फरवरी को हुई थी और उसी तारीख को फैसला आया है। मामले की केस डायरी फरवरी, 2020 में गायब हो गई थी। घटना के वादी और मुख्य गवाह का निधन हो चुका है।

फूलन देवी और गिरोह ने 14 फरवरी, 1981 को 20 लोगों को गोलियों से भून दिया था

36 में से फूलन देवी समेत 33 आरोपितों की हो चुकी है मौत, एक अब तक फरार



अभियुक्त श्यामबाबू को जेल ले जाती पुलिस। जागरण

रहे गांव के ही राजाराम ने फूलन देवी समेत 36 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इनमें से एक आरोपित मान सिंह अब तक पुलिस को पकड़ में नहीं आया। मुकदमे की सुनवाई में वादी राजाराम के साथ ही मुख्य गवाह रहे जंतर की मौत हो चुकी है।

रंजिश और मुखबिरी के शक में हुआ था बेहमई कांड

बेहमई कांड डकैत श्रीराम व लालाराम की फूलन से रंजिश व मुखबिरी के शक में हुआ था। श्रीराम व लालाराम बाबू गुजर की हत्या से नाराज थे। वे फूलन को ही हत्या के लिए जिम्मेदार मानते थे और बदला लेना चाहते थे। उन्होंने फूलन को अगवा कर लिया था, जिसके बाद हुए आतंक ने फूलन को दस्यु सुंदरी बना दिया। फूलन को शक था कि बेहमई गांव के लोग श्रीराम गिरोह को संरक्षण देते हैं। इसी आक्रोश में उसने 20 निर्दोषों की जान ले ली थी। लालाराम व श्रीराम ने विक्रम मल्लाह की हत्या कर फूलन को अगवा किया था, जिसके बाद उसने अपमानित किया गया था। उस समय फूलन की उम्र 18 साल के आसपास थी। वहां से भागकर फूलन ढाकुओं के पास मदद मांगने गईं और अज्ञान न्या गिरोह बनाया। इसके बाद उसने कसम का अतिरिक्त अलावा दो अन्य आरोपित काजी यासिर और मोहम्मद मकबूल मीर हैं।

गोतस्करों को छुड़ाने गए विहिप-बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने में की तोड़फोड़

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद

उप के औरंगाबाद में गोतस्करों को छुड़ाने गए विहिप-बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने में तोड़फोड़ की है। गोतस्करों ने पुलिस से कानपुर देहात निवासी बजरंग दल के सदस्य जिला गोरेखा प्रमुख रिशू पांडेय और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार किया था। बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उनकी पैरवी में एंबाकाटर था ने कार्यकर्ता को हवालात में बंद आरोपितों को छुड़ाने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने थाने में तोड़फोड़ की। पुलिस ने लाठी पटककर भीड़ को खदेड़ा और नौ नामजद व 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। उधर, बुधवार को गोतस्करों के चारों आरोपितों को जेल भेज दिया गया। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गांव

हरनगरपुर के पास सोमवार देर रात यूगीदा की सुरक्षा टीम ने गोवंशी पशुओं से लदे मिनी ट्रक को पकड़ा था। मामले में पुलिस ने कानपुर देहात निवासी बजरंगदल के सह जिला गोरेखा प्रमुख रिशू पांडेय उर्फ शांतनु सहित चार को पकड़ा था, जबकि दो फरार हो गए थे। रिशू को छुड़ाने के लिए कानपुर देहात व औरंगाबाद के बजरंग दल, विहिप व गोरेखा संगठन के करीब 50 लोग मंगलवार देर रात थाने पहुंचे। पुलिस से अपने साथी को लेकर बातचीत की। इसी बीच सीओ बिभूना व कई थानों की फोर्स पहुंच गईं। बातचीत के दौरान कार्यकर्ता उग्र हो गए और साथी को ले जाने के लिए हवालात की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने रोکنे का प्रयास किया तो धक्कामुक्की कर दी। वहां रखी कुर्सी आदि फर्नीचर को तोड़ दिया और बाइक को पटाटा दिया।

पाकिस्तान से चला रहे थे खेल

प्रथम पृष्ठ से आगे

गिरफ्तार किए गए चार आरोपितों के अलावा दो आरोपित अंतर्गत अल्ट्रा अहमद बट और मंजूर अहमद शाह भी हैं, जो इस समय पाकिस्तान के कराची और रावलपिंडी में छिपे बैठे हैं। ये दोनों सुरक्षाबलों से बचने के लिए 1990 में पाकिस्तान भाग गए थे। अल्ट्रा और मंजूर हैं पाकिस्तान में एमबीबीएस और इंजीनियरिंग कालेजों में कर्मचारी छात्रों के दुखिले की आड़ में टेस्ट फंडिंग के खेल में आइएसआइ की पूरी मदद करते थे। इनके अलावा दो अन्य आरोपित काजी यासिर और मोहम्मद मकबूल मीर हैं। ईटी की ओर से गिरफ्तार किए गए तीन आरोपितों में मोहम्मद अकबर बट, फातिमा शाह और सब्जार अहमद शेख हैं। फातिमा शाह ने अल जब्बार नामक ट्रस्ट बना रखा था। सब्जार शेख अंतर्गत का रहने वाला है। मोहम्मद अकबर बट हिजबुल मुजाहिदीन के उन

राष्ट्रीय फलक

जागरण संवाददाता, नैनीताल

केंद्रीय सूचना आयोग ने चर्चित आइएफएस अधिकारी और हल्द्वानी के मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी के मामले में निष्पक्ष व समुचित सुनवाई करने के निर्देश प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को दिए हैं। आयोग ने कहा, संजीव के पक्ष को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए सुना जाए और कारण सहित आदेश पारित किया जाए। साथ ही कहा, मामले की सुनवाई 30 दिन के भीतर पूरी कर अनुपालन रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए।

आइएफएस संजीव चतुर्वेदी से जुड़ा है मामला, 30 दिन में देना होगी रिपोर्ट

संजीव के अधिवक्ता सुदर्शन गौयल ने के मुताबिक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में मुख्य सतर्कता अधिकारी पद पर रहते हुए संजीव ने 2012-14 तक भ्रष्टाचार से जुड़े दो सौ से अधिक मामले उजागर किए थे। 2014 में एक तत्कालीन संसद को भूमिका की जांच की लेकर उन्होंने पीएमओ से शिकायत की थी। तब संबंधित संसद ने संजीव को एम्स के मुख्य सतर्कता

ईडी ने शुरु की पेटोएम के खिलाफ जांच

नई दिल्ली, प्रैट: ईडी ने पेटोएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के खिलाफ जांच आरंभ की जांच शुरू कर दी है। इसकी जानकारी स्वयं कंपनी ने बुधवार को शेरार बाजार को दी। कंपनी ने कहा कि ईडी उसकी पैरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) व उसकी सहायक कंपनियों से ग्राहकों से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने को नोटिस भेज रहा है। कंपनी द्वारा अधिकारियों को जानकारी, दस्तावेज व स्पष्टीकरण प्रदान किए जा रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में ईटी और वित्तीय खुफिया इकाई ने आरबीआइ से पेटोएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को ग्राहक खातों में जमा या टाप-अप स्वीकार करने से रोکنे के बारे में उसके द्वारा की गई कार्रवाई पर अपनी रिपोर्ट साझा करने के लिए विश्लेषण करने के लिए भी आरबीआइ से रिपोर्ट मांगी है कि क्या पेटोएम या पीपीबीएल ने मनी लॉड्रिंग एक्ट की धारा 13 के तहत रिपोर्टिंग इकाई के तौर पर जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किया है।

एम्स दिल्ली ले जाए जगद्गुरु रामभद्राचार्य

जागरण संवाददाता, देहरादून: तुलसी

पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज को देहरादून से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली ले जाया गया है। सिनर्जी अस्पताल के एमडी कमल गर्ग ने बताया कि उनकी ब्राईयांस सर्जरी एम्स दिल्ली में हुई थी। उनके हाट के बाल्व बदले जाने हैं। जिसके लिए उन्हें एम्स दिल्ली ले जाया गया। वह 20 फरवरी तक वापस लौट आएंगे।

पीसीबी ने मसूरी के नौ होटल कराए बंद, बिजली-पानी के कनेक्शन काटे

जासं, मसूरी

पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की अनुमति न लेने पर मसूरी के नौ होटल बंद करा दिए गए हैं। इन होटलों के बिजली-पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। पीसीबी की ओर से पूर्व में बगैर अनुमति चल रहे 27 होटलों को नोटिस भेज गए थे। हालांकि, वर्तमान में इनमें से नौ ही संचालित हो रहे थे। पीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी डा. आरके चतुर्वेदी ने बताया कि बीते वर्ष एनजीटी के निर्देश के बाद मसूरी के होटलों का निरीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि मसूरी के 282 होटलों में 27 मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं। जिन्हें समय-समय पर नोटिस जारी किए गए।



बुधवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिना अनुमति संचालित नौ होटलों की बिजली व पानी की आपूर्ति बंद कराने के साथ ही संचालन भी रोकवा दिया। पूर्व में बोर्ड ने इन नौ होटल को नोटिस देकर अनुमति लेने के निर्देश दिए थे। साथ ही होटल संचालन में पर्यावरणीय मानकों का ध्यान रखने को कहा था। कई बार नोटिस देने के बाद भी होटल स्वामियों ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। जिसके बाद कार्रवाई की गई।

7 अक्टूबर से गाजा पर इजरायली हमलों में 28,576 फलस्तीनी मारे गए हैं और 68,291 घायल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 103 फलस्तीनी मारे गए और 145 घायल हुए हैं।

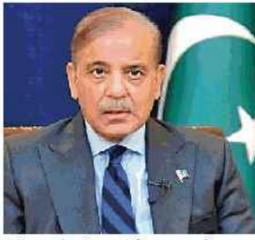
रात के अंधेरे में हुई जनदेश की चोरी खान यूनिस के नासिर अस्पताल को खाली कर रहे फलस्तीनी

इमरान की पार्टी पीटीआइ ने कहा, चुनाव परिणाम को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती

निर्दलियों को पार्टी में शामिल होने को मिलेंगे तीन दिन

इस्लामाबाद, भेट: पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए पीएमएल एन के प्रमुख शहबाज शरीफ के समर्थन में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (54) व मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट (17) आ गए हैं, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी-पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआइ) ने कहा है कि मतदान के बाद रात के अंधेरे में जनदेश की चोरी हुई। धांधली कर उसके प्रत्याशियों को हराया गया। ज्ञात हो, चुनाव में सबसे बड़ी संख्या में पीटीआइ समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर आए हैं। इन्होंने से दो ने अब शहबाज की पार्टी-पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) की सदस्यता ले ली है।

फिर तय होगा आरक्षित सीटों पर नामित करने का फाट

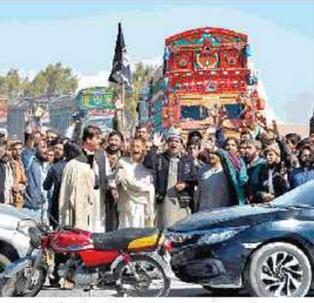


पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। फाइल/रायटर

जिन्हें नकार चुके हैं। लेकिन सत्ता के लिए ये एक बार फिर मिल गए हैं। प्रवक्ता ने कहा, पीटीआइ पूरी ताकत से इन लोगों के राष्ट्रविरोधी कार्यों का विरोध करेगी। देश को मुश्किलों से निकालने में केवल इमरान खान ही सक्षम हैं। मंगलवार को रावलपिंडी की आदियाला जेल में इमरान ने कहा था कि उनकी पार्टी आठ फरवरी के चुनाव परिणाम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। उन्होंने अपने जीवन में किसी भी चुनाव में इतने बड़े स्तर पर धांधली न सुनी न देखी। ज्ञात हो, आठ फरवरी को 265 सीटों पर हुए चुनाव में पीटीआइ समर्थित 95 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। इन्होंने देश को बर्बाद किया है और लोग

वल्चिस्तान में चुनाव में धांधली के विरोध में सड़क जाम करावी, भेट:

बलूचिस्तान प्रांत में सड़क जाम से जनजीवन ठहर गया है। चुनाव परिणाम में धांधली के विरोध बलूचिस्तान राष्ट्रीय पार्टी (मैमाल), परतूमखा मिल्ले आवामी पार्टी व हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी ने बुधवार से सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर बैरियादी जाम लगा दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिन स्थानों पर धांधली हुई है वहां फिर से मतगणना का आदेश जारी नहीं होगा तब तक जाम लगा रहेगा।



बुवार को बघेता मेहाईवे अवरुद्ध कर प्रदर्शन करते परतूमखा मिल्ले आवामी पार्टी के समर्थक। एएफपी

मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा, धांधली हुई: कट्टरपंथी मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जमायत उलेमा-ए-इस्लाम फजल ने कहा है कि आठ फरवरी के चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इसलिए वह धांधली का फायदा लेकर सरकार बनाने वाले गठबंधन में शामिल नहीं होगी और विपक्ष को नामित करने का अधिकार मिलेगा। ये आरक्षित सीटें 60 महिलाओं और 10 अल्पसंख्यकों से भरी जाएंगी। सरकार के विश्वास मत में ये नामित सदस्य भी मतदान करेंगे। नई संसद का पहला सत्र मतदान की तारीख के बाद तीन सप्ताह के भीतर अर्थात् 29 फरवरी तक बुलाने अनिवार्य है।

मरयम ने नवाज शरीफ के संन्यास की चर्चा खारिज की

इस्लामाबाद, भेट: प्रधानमंत्री पद के लिए शहबाज शरीफ का नाम प्रस्तावित होने के बाद पीएमएल एन नेता नवाज शरीफ के सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की चर्चा ने जोर पकड़ा था, लेकिन बुधवार को नवाज की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मरयम नवाज ने इस चर्चा को खारिज कर दिया। एक्स पर जारी बयान में कहा, अगले पांच साल नवाज शरीफ ने केवल सक्रिय राजनीति में रहेगे बल्कि पीएमएल एन के नेतृत्व वाली संघीय और पंजाब सरकारों की पूरी देखभाल भी करेंगे। पार्टी ने मंगलवार रात अचानक नवाज शरीफ के स्थान पर प्रधानमंत्री पद के लिए शहबाज शरीफ का नाम प्रस्तावित करने की घोषणा की थी। पार्टी ने यह कदम तब उठाया था जब तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ की सरकार को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट तैयार थे। मरयम ने कहा,

कहा, पिता ने सिद्धांतवादी राजनीति करते हुए शहबाज को मौका दिया है

दोलीं, नवाज संघीय व पंजाब सरकारों की पूरी देखभाल करते रहेंगे



मरयम नवाज। फाइल फोटो

उन्होंने पिता ने सिद्धांतवादी राजनीति करते हुए पार्टी प्रमुख शहबाज शरीफ को मौका दिया है। विदित हो कि मरयम नवाज का नाम पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा है।

यूक्रेन ने काला सागर में रूसी युद्धपोत को डुबोया

कीव, एपी: यूक्रेन की सेना ने मंगलवार को दावा किया कि उसने काला सागर में एक रूसी युद्धपोत पर जोरदार हमला किया और क्रोमिया प्रायद्वीप के शहर अलुपका के निकट उसे डुबो दिया। यूक्रेन की सैन्य इंटेलिजेंस जेयूआर ने बताया कि उसकी विशेष परिचालन इकाई 'युप 13' ने बुधवार को मगुरा वी5 समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल कर रूस के 'त्सेरन कुनिकोव' नामक युद्धपोत को डुबो दिया। दो हफ्तों में यह दूसरा बार है कि यूक्रेनी बलों ने कहा, उन्होंने काला सागर में रूसी जहाज को डुबो दिया। रूसी सेना ने कहा, मंगलवार देर रात उसने काला सागर के ऊपर छह यूक्रेनी ड्रोन को गिरा दिया।



रूसी सेना ने बुधवार की सुबह यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र के सेलीडोव शहर में मिसाइल हमले किए जिससे अवासीय इमारतों में आग लग गई। रायटर

यूक्रेन के पूर्वी डोनेस्क क्षेत्र के सेलीडोव शहर पर मंगलवार देर रात कई मिसाइल हमले किए। हमलों में एक बच्चे समेत तीन नागरिकों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि हमले से अस्पताल और

रूसी विज्ञानी कैंसर के टीके बनाने के करीब : पुतिन

मास्को, रायटर: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा, रूसी विज्ञानी कैंसर के लिए टीके बनाने के करीब पहुंच गए हैं, जो जल्द ही मरीजों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। पुतिन ने टीवी पर दिए गए बयान में कहा, हम कैंसर टीकों और नई पीढ़ी की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करने वाली दवाओं के निर्माण के बहुत करीब हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही उनका प्रभावों दंगा से चिकित्सा के रूप में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने मास्को में भविष्य की तकनीकों पर आर्थोजित कार्यक्रम में ये बातें कहीं। पुतिन ने यह नहीं बताया कि प्रस्तावित टीके किस प्रकार के कैंसर को लक्षित करेंगे और कैसे काम करेंगे। कई देश व कंपनियों कैंसर के टीकों पर काम कर रही हैं। पिछले साल ब्रिटिश सरकार ने जर्मनी स्थित बायोएन्टेक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो कैंसर उपचार प्रदान करने के लिए परीक्षण शुरू करेगा। जिसका लक्ष्य 2030 तक 10,000

रूसी राष्ट्रपति ने जल्द टीका उपलब्ध कराने का किया दावा



व्लादिमीर पुतिन ने यह नहीं बताया कि यह कैसे काम करेगा

रोगियों तक पहुंचना है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों माडर्न और मर्क एंड कंपनी एक प्रयोगात्मक कैंसर वैक्सीन विकसित कर रही हैं, जो तीन साल के उपचार के बाद मेलैनोमा (सबसे घातक त्वचा कैंसर) से मृत्यु की संभावना को आधा कर देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वर्तमान में छह लाइसेंस प्राप्त टीके हैं जो कई तरह के कैंसरों का कारण बनने वाले मानव पेपिलोमाविरस के उपचार के लिए हैं, जिनमें सर्बिकल कैंसर भी शामिल है। साथ ही हेपेटाइटिस बी के टीके भी हैं, जो लीवर कैंसर का कारण बनता है।

कैलीफोर्निया के घर में मृत मिला चार सदस्यों का भारतीय परिवार

स्यूकॉ, भेट: अमेरिका में भारतीय मूल के एक परिवार की हत्या-आत्महत्या के अंदेश की कड़ी में एक और मामला सामने आया है। कैलीफोर्निया के एक घर में चार साल के दो जुड़वां बच्चों समेत भारतीय मूल का एक पूरा परिवार मृत मिला है। इनकी पहचान आनंद सुजीत हेनरी, एलाइस प्रियंका और उनके दो जुड़वां लड़कों के रूप में हुई है। एनबीसी के रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने अभी तक औपचारिक रूप से पीड़ितों को पहचान जाहिर नहीं की है। यह घटना सोमवार को सैन माटेयो में हुई। पुलिस को 911 से काल आया था और किसी ने बताया कि उस घर से कुछ समय से कोई हलचल नहीं हुई है। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं मिले। सैन माटेयो पुलिस विभाग के जनसूचना अधिकारी जर्मी सुरेट ने बताया कि दुर्भाग्यवश घर में दो बच्चों

दंपती के अलावा मरने वालों में चार साल के जुड़वां लड़के भी

पुलिस हत्या और आत्महत्या के अंदेशों पर कर रही है जांच

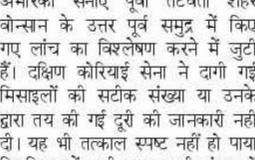
समेत चार लोगों के शव मिले। बच्चों की लाशें ब्रेडरूम में थीं और उनके शरीर पर कोई निशान नहीं हैं, जबकि भारतीय मूल के दंपती के शव बाथरूम में मिले और दोनों के शरीर पर गोलियों के निशान हैं। मौत का समय और कारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बाथरूम में ही एक नौ मिमी की पिस्तौल और लोडेड मैग्जीन मिली है। अटलत के रिपोर्ट के अनुसार प्रति ने दिसंबर, 2016 में तलाक के लिए आवेदन किया था पर फिर उस प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि पूरे परिवार के खाम्बे की यह घटना हत्या या आत्महत्या दोनों ही हो सकती है। दोनों

दक्षिण कोरिया ने कहा, उत्तर कोरिया ने दागी कूज मिसाइलें

सियोल, एपी: उत्तर कोरिया ने बुधवार को समुद्र में कई कूज मिसाइलें दागीं। जनवरी से लेकर अब तक यह उसका यह पांचवां परीक्षण है। दक्षिण कोरियाई सेना ने कहा है कि हथियारों के बढ़ते प्रदर्शन से क्षेत्र में तनाव और बढ़ रहा है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ आफ स्टाफ ने कहा कि दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी सेनाएं पूर्वी तटवर्ती शहर वोन्सान के उत्तर पूर्व समुद्र में किए गए लांच का विश्लेषण करने में जुटी हैं। दक्षिण कोरियाई सेना ने दागी गई मिसाइलों की सटीक संख्या या उनके द्वारा तय की गई दूरी की जानकारी नहीं दी है। यह भी तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया कि मिसाइलें जर्मनी या समुद्री संसाधनों से दागी गईं। ज्वाइंट चीफ आफ स्टाफ ने कहा, हमारी सेना ने निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है और उत्तर कोरिया की आगे की गतिविधियों पर गहरी दृष्टि रखने के लिए अपने अमेरिकी साझेदारों के साथ काम कर रही है।

गारंभिक त्वरित गणना में प्रतिद्विंदियों पर मिली वदत

अमेरिका-चीन भी चुनाव पर वनाए हुए हैं अपनी नजर



इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बुधवार को एक पोलिंग स्टेशन पर मतदान करते राष्ट्रपति जोको विडोदे और प्रथम महिला इरिगाना। रायटर

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बुधवार को एक पोलिंग स्टेशन पर मतदान करते राष्ट्रपति जोको विडोदे और प्रथम महिला इरिगाना। रायटर

युद्ध होने पर नाटो में शामिल देशों की रक्षा करेगा अमेरिका : बाइडन

वाशिंगटन, भेट: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंगलवार को एक बार फिर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के प्रति प्रतिबद्धता जताई। बाइडन ने हाल ही में अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई टिप्पणियों को खतरनाक बताते हुए कहा कि 74 साल पुराना यह संगठन अमेरिका के लिए पवित्र प्रतिबद्धता है। जब तक में राष्ट्रपति हूँ और यदि पुतिन नाटो में शामिल किसी भी देश पर हमला करते हैं तो अमेरिका नाटो क्षेत्र के हर इंच की रक्षा करेगा। हाल ही में दक्षिण कैरोलिना में एक रैली में ट्रंप ने कहा था कि वह नाटो सहयोगियों से अपना रक्षा खर्च बढ़ाने को कहेंगे अन्यथा उन देशों पर आक्रमण करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रोत्साहित करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंगलवार को कहा कि जब अमेरिका जवान देता है तो उसका कुछ मतलब होता है। जब हम कोई वुदा करते हैं तो हम उसे निभाते हैं और नाटो हमारे लिए पवित्र प्रतिबद्धता है। हालांकि ट्रंप इसे बोझ के रूप में देखते

अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्रंप की टिप्पणियों को वताया खतरनाक

दक्षिण कैरोलिना में पूर्व राष्ट्रपति ने नाटो पर की थी विवादित टिप्पणी



अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन। एपी

हैं। उन्होंने कहा, जब वह नाटो को देखते हैं तो उन्हें अमेरिका और पूरी दुनिया की रक्षा करने वाला गठबंधन नहीं दिखता है। वह नहीं समझते हैं कि नाटो स्वतंत्रता, सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता के मूलभूत सिद्धांतों पर बना है। बाइडन ने ट्रंप की टिप्पणियों को नाजगन्य जताते हुए कहा कि ट्रंप के लिए सिद्धांत मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए सब कुछ लेन-देन है।

